13.06 hrs.

BIHAR BUDGET, 1980-81—GENERAL DISCUSSION DEMAND* FOR GRANTS ON ACCOUNT AND 1980-81 SUPPLEMENTARY DEMANDS* FOR GRANTS (BIHAR), 1979-80

MR. CHAIRMAN : The House will now take up Items 10, 11, and 12 of the Order Paper relating to the Bihar Budget, for which 2½ hours have been allotted. Hon. members who have tabled cut motions to the Demands for grants on Accounts—Bihar Budget, if they desire to move their cut motions, may send slips to the Table within 15 minute indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

Motions moved :

"That the respective sums not exceeding the amount shown in the third column of the Order Paper relating to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar, *on account*, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1981, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 1, 3 to 8, and 10 to 28."

"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1980, in respect of the following demands entered in the second column thereof — Demands Nos. 1, 3 to 6, 10 to 26, and 28."

Demands for Grants on Account (Bihar) for 1980-81 submitted to the vote of Lok Sabha.

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account submitted to the vote of the House.
		Rs.
1	State Legislature	68,37,500
3	Council of Ministers, Election, Secretariat and District Administration	8,51,12,966
4	Administration of Justice and other Social and Community Services	2,01,49,266
5	Land Revenue and Relief on Account of Natural Calamities	12,81,03,000
6	Taxes, Treasury, Pension and Printing	7,98,87,966
7	State Excise Duty	63,00,000
8	Taxes on Vehicles and Road and Water Transport Services	83,83,333
10	Police, Protection from fire and Other Administrative Services	20,78,42,100
11	Jails	2,47,00,000
12	Public Works, Housing and Civil Aviations	16,96,61,833
13	Education and Art and Culture	63,29,80,066
14	Health and Family Welfare	17,93,65,966
15	Public Health, Sanitation, Water-supply and Urban Development	14,84,82,040
16	Information, Publicity and Tourisms	48,91,666
17	Labour and Employment	1,54,14,333
18	Social Security and Welfare	8,43,12,233
19	Co-operation	6,38,00,173
20	Agriculture and Animal Husbandry	24,48,46,700
21	Minor Irrigation	7,26,80,666
22	Dairy Development	36,93,633
23	Fisheries	55,97,666
24	Forest	3,71,37,333
25	Community Development	17,29,35,933
26	Industries	5,68,23,166
27	Mines and Minerals	46,51,666
28	Irrigation and Electricity	82,97,85,666

*Moved with the recommendation of the President.

Supplementary Demands for Grants (Bihar) for 1979-80 submitted to the Vote of Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House.
		Rs.
1	State Legislature	13,27,500
3	Council of Ministers, Election, Secretariat and District Administration	52,17,000
4	Administration of Justice and other Social and Community Services	26,40,000
5	Land Revenue and Relief on account of Natural Calamities	1,61,2[illegible]
6	Tax, Treasury, Pension and Printing	29,[illegible],000
10	Police, Fire protection and Control and other Administrative Services	6,17,9[illegible],760
11	Jails	5
12	Public Works, Housing and Civil Aviation	15
13	Education and Art and Culture	1,79,145
14	Health and Family Welfare	55,79,210
15	Public Health, Sanitation, Water-supply and Urban Development	6,79,68,035
16	Information, Publicity and Tourism	5,34,655
17	Labour and Employment	20
18	Social Security and Welfare	1,68,04,505
19	Co-operation	2,74,72,800
20	Agriculture and Animal Husbandry	5,43,36,695
21	Minor Irrigation	1,25,00,005
22	Dairy Development	54,00,000
23	Fisheries	15,00,000
24	Forest	67,00,005
25	Community Development	9,16,50,005
26	Industries	2,47,92,530
28	Irrigation and Power	12,22,54,000
	TOTAL	52,77,24,890

13.07 hrs.

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : सभापति महोदय, हमारा बिहार गांवों का राज्य है। विगत 32–33 वर्षों में, आजादी के बाद से, इन गांवों की ओर किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं झांका। शासक केवल शहरों की ओर देखते रहे, यहां के रहने वाले किसानों, खेतिहर मजदूरों, हरिजनों, गिरिजनों और अल्प-संख्यकों की किसी ने कोई खोज-खबर नहीं ली। बिहार की खेती प्यासी है, उसको कभी भी भरपेट पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, डीजल नहीं मिला, खाद नहीं मिला।

सभापति महोदय, बिहार का बिजली बोर्ड लूट का अखाड़ा बना हुआ है। जो भी अध्यक्ष बन कर जाता है, वह लूटता है, ईमानदार अफसरों का वहां अभाव है। यदि भूल से कोई ईमानदार अफसर चला जाता है तो उसे वहां से हटने के लिए बाध्य होना पड़ता है, वह वहां पर टिक ही नहीं पाता। बिहार को कम से कम 12–13 सौ मैगावट बिजली की जरूरत है, लेकिन मिलती है—केवल 300 से 400 मेगावट और वह भी खेती के लिए नहीं, छोटे उद्योगों के लिए नहीं, कुटीर-उद्योगों के लिए नहीं, बल्कि बड़े-बड़े शहरों के लिए।

बिहार में इस समय भी भयंकर सूखा है। धान की फसल मारी गयी है, रबी की फसल चौपट होने वाली है। सूखे इलाकों में अपाहिज या अन्य गरीब खेतिहर मजदूर आज भूखे मर रहे हैं, इनकी ओर कोई देखने वाला नहीं है, कोई खोज-खबर लेने वाला नहीं है। नौकरशाही आराम से रौबदार शासन में मस्त है, चैन की बंसी बज रही है। हर जिले में भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अखबारों में आ रहा है कि भूख से मरने वाले जहां-तहां लूट भी करने लगे हैं, चारों ओर अशान्ति और तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसलिए शीघ्र-लाल-कार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। जन-श्रम-योजनाएं चलानी चाहिएं ताकि बेकारों को काम मिल सके। हर गांव में राशन की दुकानें खोलनी चाहिएं और लोगों की क्रय-शक्ति को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उपाय करने चाहियें।

इन्दिरा जी और उनकी कांग्रेस इस बात को जानती है कि बिहार में आज किस तरह की स्थिति है। बिहार में 1974 में विद्यार्थियों और नौजवानों ने आन्दोलन किया था, लड़ाई छेड़ी थी। किस लिए? उनके सिर्फ तीन मुद्दे थे—पहला शिक्षा में आमूल परिवर्तन करो, दूसरा बेकारी को दूर करो और तीसरा भ्रष्टाचार को खत्म करो। उनकी मांगें ठीक थीं, जायज थीं, लेकिन इनके बदले आपने उन्हें बड़ी-बड़ी यातनाएं दीं, लाठी मारी, गोली मारी, जेलों में डाला, मीसा लगाया और फिर एमर्जेन्सी लगाई।

13.09 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

आज भी वे सारी की सारी मांगें ज्यों की त्यों मुंह बाये खड़ी हैं। आपके सामने यह सवाल खड़ा है कि क्या आप शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं या नहीं जिस से बढ़ती बेकारी दूर हो सके। आज बेकारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यदि आप शान्ति से सरकार चलाना चाहते हैं, तो बिहार की गरीबी को, वहां की बेकारी को आप को दूर करना होगा। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या 70 प्रतिशत से अधिक है। यह आंकड़ा 1977 का ही है।

बिहार में भयंकर सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी है। यही कारण है कि गांव गांव में झगड़ा है, लड़ाई है, तनाव है और हर गांव में लोग लड़ने के लिए उतावले हैं, चाहे वह पारस-बीघा का कांड हो और चाहे वह पिपरा का कांड हो। ये सारे के सारे कांड सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी की वजह से, ना-बराबरी की वजह से हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार शीघ्र इस ओर ध्यान दे। इसके लिए सरकार को गांवों में जाना होगा और वहां के गावों की हालत को देखना होगा कि वहां कितने प्रकार की कुरीतियां फल रही हैं। हर गांव की सड़कों का पक्कीकरण करना होगा। हर गांव में पैखाने, स्नानघर बनें, जच्चा घर बनें और दवाओं के लिए प्रबन्ध हो। आप को वहां हर गांव का विद्युतीकरण करना होगा। सिंचाई और पीने का पानी देना होगा।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरों के लिए 6 महीनों का काम गांवों में ही देने का प्रबन्ध हो। यह कैसे होगा? इसके लिए आपको गृह उद्योग और कुटीर उद्योग लगाने होंगे। गांवों में बसने वाले चमार, लोहार, सोनार, बढ़ई, दर्जी, बुनकर, दफाली आदि कारीगरों को आधुनिक और सस्ते औजार देने होंगे और उनके लिए पूंजी मुहैया करनी होगी।

जो सीमा सम्बन्धी कानून है, वह बोगस है, एक आडम्बर मात्र है। इसलिए उसमें संशोधन किया जाए और आपको एक ऐसा कानून बनाना होगा, जिससे लोगों को फायदा हो। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 23 प्रतिशत बड़े किसानों के पास 70 प्रतिशत भूमि है और बाकी 77 प्रतिशत किसानों के पास केवल 30 प्रतिशत भूमि है। इसको शीघ्र सरकार को ठीक करना होगा।

गांवों के लिए जो योजनाएं स्वीकृत हैं, चाहे वे सिंचाई की हों, बांध या तटबंध की हों, पुल-पुलियां की हों, उनको युद्ध स्तर पर पूरा करना होगा। मैं एक तटबंध का जिक्र, जो मेरे क्षेत्र में आता है, करना चाहता हूं और उस का हवाला देना चाहता हूं। 1973 में योजना आयोग

[श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा]

ने एक योजना की स्वीकृति दी। यह योजना, बकसर-कोइलवर तटबन्ध योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना पांच वर्ष में पूरी होनी थी। यानी इस योजना को 1978 में पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। 10 करोड़ रूपये की यह योजना थी लेकिन अब तक उस में केवल एक-चौथाई ही काम हुआ है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि वह योजना ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। नये प्राक्कलन के हिसाब से उस पर 30 करोड़ रूपये लगेंगे। अब फिर प्राक्कलन बदलने वाला है और इससे भी अधिक खर्च पड़ने वाला है। यह परियोजना 107 किलोमीटर लम्बी है और गंगा नदी के बायें तट पर बक्सर से कोइलवर तक 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र को इससे लाभ होने वाला है। कुछ काम हुआ है और कुछ बाकी है। इसके पूरा न होने से किसानों को अपार क्षति हो रही है। हर वर्ष 40–45 करोड़ रूपये की क्षति बाढ़ के कारण फसलें मारे जाने से किसानों को हो रही है लेकिन अभी तक उस ओर कोई ध्यान कारगर ढंग से नहीं दिया जा रहा है। इस भूमि के लिए हाई पावर पम्पिंग सैट गंगा में लगाने चाहिएं, सरकारी नलकूप लगाने चाहिएं और नयी व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार बिहार के अन्दर अनेकों योजनाएं लम्बित हैं जिन्हें शीघ्र पूरा करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के देखा-देखी हर छोटे-बड़े शहरों में युवतियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। बिहार की एक घटना है। सिवान में विगत 10 तारीख की रात्रि में गाडी छूट जाने के कारण एक महिला जिसके साथ एक नौकर भी था, वाम्बे लाज में ठहर गई। उस नौकर को अलग कर के दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया और उस महिला के साथ सात युवकों ने बलात्कार किया। दूसरे दिन दस बजे उसे छोड़ा गया। अभी वे लोग फरार हो गये हैं। उन पर शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए।

गुण्डे यह सोचते हैं कि देश की राजधानी में जब ऐसा हो रहा है और गुण्डों पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो फिर दूसरे बड़े या छोटे शहरों में उन्हें कौन रोकेगा। हत्या, लूट, डकैती, आतंक और भ्रष्टाचार वर्तमान राष्ट्रपति शासन में और अधिक बढ़ गये हैं। इसलिए शीघ्र कोई कार्यवाही कीजिए ताकि ये रुकें।

श्री केदार पांडे (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी आबादी 6 करोड़ है और यह तीन हिस्सों में बंटा हुआ है — उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, छोटा नागपुर और संथाल परगना। यह एक फ्यूडल स्टेट रहा है एक कंजरवेटिव स्टेट रहा है। इसको एक हार्ड नट स्टेट भी कहा जा सकता है क्योंकि वहां विकास कार्य कम हुए हैं।

यहां पर ढाई-तीन साल पहले जब जनता पार्टी की हुकूमत आयी तो बिहार में कास्टिज्म और भी जोरों से पनपा। कास्टिज्म की कुछ जड़ तो पहले ही वहां थी लेकिन सब से ज्यादा इस ने उग्र रूप धारण किया जब से जनता पार्टी की हुकूमत बिहार में बनी। जब वहां पर बेकवर्ड क्लास और फारवर्ड क्लास का उग्र रूप सामने आया तो उसमें जातियता का पुट था। बिहार एक गरीब स्टेट है, पुअर स्टेट है। इस के बारे में सब जानते हैं कि बिहार की आबादी के 76 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। जब कि जहां इस देश के शहरों में बिलो पावर्टी लाइन का परसेण्टेज 45 और देहातों में बिलो पावर्टी लाइन का परसेण्टेज 55 परसेण्ट है वहां हमारी स्टेट बिहार में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का परसेण्टेज 76 है। यह यहां की गरीबी की हालत है। पिछले तीन सालों से यहां विकास के काम एकदम बिल्कुल ठप्प है। जब से वहां जनता पार्टी की हुकूमत बनी तब से वहां विकास का एक भी काम नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ वह पहले की हुकूमत के अन्दर हुआ और उस में ऐसे लोग भी शामिल थे जो आज कांग्रेस आई में नहीं हैं, दूसरी हुकूमत में थे। कांग्रेस की जो हुकूमत थी उस में वे लोग भी थे। उस वक्त कुछ बात बनी। लेकिन विकास का काम जब से जनता पार्टी की हुकूमत बनी तब तो एक दम ठप्प ही हो गया। यह सही बात है, ईमानदारी की बात है। यह इधर का इतिहास है,। इसके पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी, जो कुछ भी विकास का काम हुआ वह उस हुकूमत में ही हुआ। इधर सब से बडी बात यह रही कि विधि व्यवस्था ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिल्कुल चौपट हो गई। जब ला एण्ड आर्डर ही न रहे तो फिर विकास की बात क्या सोची जा सकती थी। ला एण्ड आर्डर की बात यह है कि इसको इनफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है दू एनी फर्दर डिवेलेपमेंट एक्टीविटीज। अब ला एण्ड आर्डर स्टेट सब जैक्ट है। जब से जनता पार्टी की हुकूमत बनी तब से ला एण्ड आर्डर ही ठप्प हो गया। ला एण्ड आर्डर के बारे में स्थिति यह है कि जो मुख्य मंत्री बनता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है, उसका यह पोर्टफोलियो होता है। लेकिन जो जनता पार्टी के मुख्य मत्री बने वे ला एण्ड आर्डर के मामले में बिल्कुल ही सुभान अल्लाह साबित हुए। यह इनकी हालत रही जिस की वजह से चोरियां, डकैतियां, लूटपाट सब शुरू हुआ, मर्डर हुए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिहार एक कंजर्वेटिव स्टेट है, कास्ट रिडन स्टेट है, वहां घोर गरीबी है, तरह तरह की बीमारियां हैं। अब उस में क्या होगा ? मर्डर होंगे, खून खराबे होंगे, प्रोग्रेस कुछ नहीं होगी। जब ला एण्ड आर्डर नहीं है तो विकास की कल्पना करना बेकार है।

दस दिन पहले प्रेजीडेंट्स रूल हुआ है। यह तो जनता पार्टी ने जो कुछ किया उसी का कंटिनूएशन है अभी तक, उसका एनर्शिया है, लिगेसी है, वही चल रहा है। हम चाहते हैं इस तरह की चीजों को रोकें। लेकिन रोकते रोकते कुछ तो यह खिंच

ही आता है। यही सही स्थिति है। इसलिए यह सोचा गया कि अब इन से चलने वाला नहीं है और दस पंद्रह दिन पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मैं कह चुका हूं कि बिहार बुनियादी तौर पर कास्ट रिडन स्टेट है, कंजर्वेटिव स्टेट है, फ्यूडल स्टेट है। यह पृष्ठभूमि उसकी है। उस पृष्ठभूमि में विकास की बात सोचें तो अच्छी बात है लेकिन वह हुआ नहीं।

जमीन का सवाल सब से बड़ा सवाल है। अगर जमीन का सवाल आप हल कर लें तो बहुत दूर तक मामला हल हो जाए। जब मैं 1972 में मुख्य मंत्री था तब हमने लैण्ड सीलिंग एक्ट बनाया था। उसके मुताबिक काम भी हुआ। एक लाख से अधिक एकड़ जमीन बांटी भी गई। उसके बाद भी जब कांग्रेस की हुकूमत रही उसने कुछ काम किया। लेकिन जब जनता पार्टी की हुकूमत आई तो जो जमीन लोगों को मिली थी वह भी उन से छीन ली गई। इसके अलावा लैण्ड सीलिंग एक्ट का इम्प्लेमेण्टेशन ठप्प हो गया। इस दिशा में जनता पार्टी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और लैण्ड सीलिंग एक्ट को लागू किया जाए, इसके बारे में कुछ नहीं किया। इस एक्ट में उसने कोई संशोधन भी नहीं किया, इसको जैसे का तैसा रखा। ये डरते थे कि जिस आधार पर हम जीत कर आए है, वह आधार ही खत्म हो जाएगा अगर हमने इस एक्ट को लागू किया और हमारे जो मास्टर है वे नाराज हो जाएंगे। इस वास्ते इस एक्ट को एक दम लागू नहीं किया गया।

हम लोगों ने मिनिमम वेजिज टू दी एग्रीकलचरल लेबरर्ज को भी लागू किया लेकिन जनता पार्टी ने इसको भी लागू नहीं किया। अगर आप गरीबी दूर करना चाहते हैं, अगर आप गांवों की बात कहते हैं तो उसके लिए यह बहुत जरूरी चीज है कि एग्रिकलचरल लेबर को मिनिमम वेज मिले। कांग्रेस की हुकूमत ने इसको लागू किया और इसको ले कर गांवों में कुछ टेंशन भी बढ़ा जो कि नैचुरल था, क्योंकि एग्रिकलचरल वर्कर्ज को मिनिमम वेज देने की और इसको लागू करने की बात जब आप करते है तो जो इससे एफैक्टिड होते हैं वे परेशान होते हैं। जमीन के बंटवारे की बात जब हम करते हैं तो ज्यादा जमीन वाले हम से घबड़ाते है। हम चाहते हैं कि इस देश में समाजवाद आये। हम सब को खुश नहीं कर सकते, हैव्ज को भी खुश करें और हैव-नाट्स को भी खुश करें यह मुमकिन नहीं है, दोनों नहीं हो सकते। इसलिए वैस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग हम से जरूर नाराज होंगे। यही वजह हुई कि गांवों में भी उथल पुथल हुई।

अगर जनता पार्टी ने यह दो काम किये होते, करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लैण्ड-सीलिंग को लागू करें, यह संभव ही नहीं था इनके लिए और एग्रीकल्चरल लेबर को मिनिमम वेज मिले, यह भी संभव नहीं हुआ। यह जो पारसबीघा, दोहिया या पिपरा वाले कांड हैं, यह उसी का आउट-कम है। यह इकनामिक इश्यू है, सोशल इश्यू बहुत कम है लेकिन कुछ लोगों ने इस इकनामिक इश्यू को ले कर कास्ट इश्यू बना दिया। लेकिन रूट काज़ है इकनामिक इश्यू, मिनिमम वेज इश्यू। लैण्डलैस एग्रीकल्चरल लेबर को मिनिमम वेज मिले यह इश्यू है और इसी का आउट-कम है कि फलां कास्ट वाले ने फलां कास्ट वाले को मारा।

कांग्रेस का जो 20-सूत्री कार्यक्रम है, उसके मुताबिक लैण्डलैस पीपल जाग गये, उन्होंने मिनिमम वेज की मांग की, जमीन का बंटवारा मांगा। उनमें जागृति पैदा हुई। जो हैव्ज थे, जो लैण्ड-लार्डज़ थे, वे कंजरवेटिव ख्याल के और फ्यूडल विभाग के थे, उन्होंने इसको बर्दाश्त नहीं किया, इसीलिए झगड़ा हुआ है। उन्होंने इसको कास्ट का कलर दिया, हरिजन और गैर-हरिजन की बात की। हरिजन मीन्स ह्वाट। एग्रीकल्चरल लेबर जो हमारे साथ थे 68 लाख एग्रीकल्चरल लेवर हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जमींदार उनको मारते पीटते है।

श्री केदार पांडे : वही कहता हूं। आप तो जनता पार्टी में नहीं थे, सी० पी० एम० में हैं। लेकिन उसी में थे, आपको तो सोचना चाहिए था, लेकिन सोचा नहीं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर बिजली स्टेट में न रहे तो विकास क्या होगा? जनता पार्टी की हुकूमत जब आई तो बिजली ठप्प हो गई। जो भी बिजली मिलती थी, वह सब गायब। बिहार की हालत क्या है, वहां 765 मेगावाट बिजली की रेटेड कैपेसिटी है। लेकिन वह रेटेड कैपेसिटी थी, वहां के इंजीनियर्स ने डी-रेट किया और डी-रेटेड कैपेसिटी 650 मेगावाट है अप-टू-डेट। लेकिन जैनरेट कितना होता है, 250 और 275। लेकिन बिहार की बिजली की मिनिमम नीड है 400 और 425 मैगावाट की। वहां एग्ज़िस्टिंग इण्डस्ट्री की हालत खराब है, न्यू इण्डस्ट्री की बात तो सोचना बेकार है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात बेकार है, क्योंकि बिजली नहीं, डीज़ल तो मिलता ही नहीं, कैरोसिन और चीनी की हालत खराब है। ला एण्ड आर्डर की बात मैंने बताई, वह तो नेशनल फिनोमिनन है लेकिन स्पेशल फीचर जो बिहार का है, मैंने उसके बारे में आपसे जिक्र किया। ये जितने सवाल हैं, उनके पीछे इकानोमिक इश्यूज हैं। मुख्य प्रश्न लैण्ड हंगर का है। इस लिए लैण्ड और मिनिमम वेज का इन्तज़ाम करना चाहिए।

यह जो बजट आया है, वह केवल चार महीने के लिए। मैं इसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब बिहार में पापुलर हुकूमत होगी, तो फिर अच्छे दिन आयेंगे।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के 1980-81 के बजट का चार महीने का लेखानुदान स्वीकृति के लिए सदन के सामने रखा गया है, जिसकी राशि 3,29,43,00,000

(श्रीमती कृष्णा साही)

रुपये से कुछ ऊपर है । मैं इसका समर्थन करती हूं। इसके साथ-साथ मैं कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार उस दिशा में ठोस और कारगर कदम उठायेगी।

बजट का 60 प्रतिशत भाग विद्युत, सिंचाई एवम् अन्य विकास योजनाओं के लिए है । मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि मात्र राशि की स्वीकृति हो जाने से ही प्रशासन अच्छा नहीं हो सकता है, विकास का काम नहीं हो सकता है । जनता पार्टी के शासन-काल में बिहार की आर्थिक स्थिति दयनीय ही नहीं हुई, बल्कि बिहार विकास और प्रगति के मामले में दस बरस पीछे चला गया । इसकी पुष्टि के लिए मैं सदन के सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती हूं ।

1970-80 में सिंचाई विभाग को अपनी योजनाओं के लिए 106 करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी थी । अभी तक मात्र 40 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हो पाये हैं । बाकी के 60 करोड़ रुपये या तो सरेंडर हो जायेंगे या उन्हें नून की तरह समाप्त कर दिया जायेगा । मैंने इस सम्बन्ध में बिहार विधान सभा में प्रश्न उठाया था और उस समय की सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था । लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने इस तरफ़ कुछ ध्यान नहीं दिया । उसके पास इन बातों के लिए समय ही नहीं था । पहले साम्प्रदायिक दंगे तो हुआ करते थे, लेकिन जात-पात का इस तरह का नंगा नाच हुआ कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गये ।

बिहार में 587 ब्लाकों में से 316 ब्लाक जनता पार्टी के शासन-काल में अकाल-ग्रस्त घोषित किये गये थे, लेकिन अकाल संहिता, फ़ैमिन कोड, के अनुसार कहीं भी राहत का काम नहीं हुआ । 66,000 गांवों में से 40,000 गांव आज भी अकाल-ग्रस्त हैं और वहां की स्थिति बहुत ही दयनीय है ।

बिहार के प्रति भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री चरण सिंह, ने जो रुख अपनाया, उसके बारे में भी मैं कुछ बातों को सदन के सामने रखना चाहती हूं । बिहार को सूखे से बचाने के लिए मात्र 15 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई, जब कि सारे देश में 250 करोड़ रुपये का वितरण किया गया था । बिहार में प्रति-मास 40,000 एम टी कैरोसीन तेल की आवश्यकता है, लेकिन लोक दल के शासन-काल में 20,000 एम टी से ज्यादा नहीं मिला, जब कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, श्री शरद पवार, को खुश करने के लिए 65,000 एम टी कैरोसीन तेल प्रति-मास दिया गया ।

मैं अपनी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इस प्रकार की पंगु और अक्षम सरकार को बर्खास्त कर दिया । उस सरकार पर से जनता का विश्वास उठ गया था, क्योंकि विकास का सारा काम ठप्प पड़ा हुआ था । पूरे पूर्ण विश्वास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में बिहार का चतुर्मुखी विकास अवश्य होगा ।

हमारे प्रांत में बिजली के सम्बन्ध में टेन्य लोड सरवे कमेटी का सर्वेक्षण हुआ । उसने रिपोर्ट दी कि इस समय बिहार को 400 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, लेकिन जैसा कि हमारे नेता, श्री केदार पांडे, ने बताया है, हमारी इनस्टाल्ड कैपेसिटी 735 मैगावाट है, जब कि उत्पादन 300 मेगावाट से ज्यादा नहीं होता है । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहती हूं कि यदि बिहार की गरीबी को दूर करना है, बिहार की प्रगति करनी है, बिहार को सब तरफ से आगे बढ़ाना है तो बिजली के उत्पादन की ओर ध्यान देना होगा, छोटे छोटे बिजली घरों का निर्माण करना होगा और जो हमारा बिजली का उत्पादन है उस को किस तरह से बढ़ाया जाय उस दिशा में कारगर कदम उठाने पड़ेंगे ।

बिहार पर केन्द्र का एवं अन्य संस्थानों का करीब 1300 करोड़ कर्ज है । प्रति वर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये सूद की अदायगी करनी पड़ती है । ऐसे गरीब प्रान्त के लिए यह बहुत बड़ा बोझ है । योजना मद में हमें जितनी केन्द्र से सहायता नहीं मिलती उससे अधिक हमें सूद के रूप में देना पड़ता है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ अपने सुझाव देना चाहती हूं ।

मेरा सुझाव है कि बिहार के फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम को सेंट्रल सेक्टर में ले लिया जाय । आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन को सेंट्रल सेक्टर में ले लिया गया है । उसी तरह से हमारे देश में बाढ़ से जितनी भी क्षति होती है उस की एक तिहाई क्षति बिहार को होती है । इसलिए बिहार के जितने साधन हैं वह फ्लड प्रोटेक्शन में समाप्त हो जाते हैं । वह जो हमारे साधन फ्लड प्रोटेक्शन में समाप्त हो जाते हैं उन को हम विकास में खर्च कर सकते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि गंगा बेसिन और फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम को सेंट्रल सेक्टर में लिया जाये ।

दूसरा सुझाव है कि बिहार पर जो केन्द्र का 11 सौ करोड़ का कर्ज है उसे राइट आफ किया जाय । यह अगर टेकनिकल डिफिकल्टी के कारण न हो सके तो मोरेटोरियम दे दिया जाय । गंगा ब्रिज जो वहां बन रहा है उस के बाकी काम को सेंट्रल सेक्टर में लिया जाय और आगे जो भी पुल बनने वाला है उसको भी लिया जाय क्यों कि इतनी बड़ी राशि बिहार जैसे गरीब प्रान्त के लिए खर्च करना सम्भव नहीं है । इसलिए इस को सेंट्रल सेक्टर में लिया जाय ।

आप जानते हैं मोकामा और बड़ैया की ताल योजना करोड़ों की है । उस से बिहार अपने तो अन्न के मामले में आत्म-निर्भर होगा ही, दूसरे प्रान्तों को भी अन्न दे सकता है । वह करोड़ों की राशि की योजना वर्षों से पड़ी हुई है, तकरीबन

25 साल तो हो ही गए होंगे। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि मेरे इन सभी सुझावों को माना जाय ताकि बिहार का चतुर्दिक विकास हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं देगी बल्कि बिहार की प्रगति के लिए, बिहार में जो गरीबी और अमीरी का असंतुलन है उस को दूर करने के लिए काम करेगी। वहां क्या नहीं है ? वहां खनिज पदार्थ है, वहां गंगा नदी है, जल है, मैगनीज है, लोहा है, कोयला है, सभी कुछ है, फिर भी उस की प्रगति नहीं हो पाती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देती हूं कि आप ने मुझे समय दिया।

SHRI ANANDA PATHAK (Darjeeling): In this Budget I do not see any ray of hope for the down-trodden people of Bihar.

Sir, the budget does not reflect the urges and aspirations of the people as they have no say in the formulation of this budget. The Central government has undemocratically dismissed the duly elected governments and the Assemblies in Bihar and other eight States and has thereby attacked the very federal structure of our country as enshrined in the Constitution of India. The action of the Central government was not only undemocratic but it smacks of a growing tendency towards authoritarianism. This action of the Central government was politically motivated and that is why the Budget has failed to give any indication of raising the living standard of the common people in general and of the toiling masses in particular.

Poverty and unemployment is rampant and it is the result of the capitalist path of development pursued by the ruling class for the last 32 years. But there is no indication of changing this path. And there is no indication of raising the minimum wages of the agricultural labourer which is very low in Bihar.

Atrocities on Harijans, Adivasis and the weaker sections of the society is a common feature in Bihar. But there is no indication in the Budget of the remedial measures the Government propose to take to put an end to such atrocities. On the other hand, such atrocities are mounting as we saw in the recent incident of Pipra. Sir, the general law and order situation is deteriorating since the imposition of President's rule in Bihar. You claim that the 20-Point Programme is the panacea of all the diseases of society but valuable human rights are being trampled underfoot and nothing is being done to ensure this right to the people.

In Bihar, abundance of coal is there which is called Black Gold, but the living condition of workers working in those coal mines is miserable and no concrete proposals for improving their lots have been made in the Budget.

Bihar is mostly inhabited by tribals, adivasis, but they are totally neglected by all the successive Governments. The fate of scheduled castes and scheduled tribes is also not good. No concrete proposals to raise the ir living standards and improve their social and cultural lives have been made in the Budget.

Feudalism, caasteism and communalism have gripped the whole political life of Bihar, but no remedial measures have been proposed to remove this cancerlike disease of the society.

So, I demand that provision for some far-reaching measures should be made in the Budget like rapid land reforms, land to the tillers and exemption of land rent for the smaller and marginal holdings. You should write off all the dues on loans against the poor peasants. Extensive food for work programme should be undertaken. Long term loan at cheaper interest for the agricultural inputs should be given to them. Unemployment allowance should be given to the unemployed youth. Measures for the minimum wages for agricultural labourers and all industrial workers, bonus to all workers and employees including State Government employees, free education at least upto Class X and setting up of more industries and industrial development etc. should be adopted. I find nothing in this Budget.

Therefore there is no point in supporting this budget. With these words, I conclude.

SHRI KAMLA MISHRA MADHUKAR (Motihari) : I beg to move :

"That the demand for grant On Account under the head Jails be reduced by Rs. 100"

[Failure to improve the condition of jails in Bihar. (9)]

"That the demand for grant On Account under the head Jails be reduced by Rs. 100"

[Failure to check irregularities in the jails of Bihar. (10)]

"That the demand for grant On Account under the head Jails be reduced by Rs. 100"

[Failure to provide modern lavatories and other amenities in the Central Jail of East Champaran. (11)]

[Shri Kamla Mishra Madhukar]

"That the demand for grant On Account under the head Education and Art and Culture be reduced by Rs. 100"

[Need to construct buildings for Primary Schools at Chalia, Dipra, Sheikhupuri and Brahman Toli of East Champaran District. (12)]

"That the demand for grant On Account under the head Eduction and Art and Culture be reduced by Rs. 100"

[Need to carry out repairs in buildings of hundreds of Primary Schools of East Champaran. (13)]

"That the demand for grant On Account under the head Education and Art and Culture be reduced by Rs. 100"

[Need to carry out repairs in students hostel building and teachers quarters of Kesaria Middle School in East Champaran District. (14)]

"That the demand for grant On Account under the head Social Security and Welfare be reduced by Rs. 100"

[Failure to provide water and housing facilities to Harijans and agricultural labourers in Bihar (15)]

"That the demand for grant On Account under the head Social Security and Welfare be reduced by Rs. 100"

[Failure to take proper action in the cases of strocities on Harijans and cases of arson in village Phalmar, District East Champaran. (16)]

"That the demand for grant On Account under the head Minor Irrigation be reduced by Rs. 100"

[Failure to check irregularities in the Minor Itrigation Department in East Champaran District. (17)]

"That the demand for Grant on Account under the head fisheries be reduced by Rs. 100"

[Failure in developing the lakes of District East Champaran for fisheries. (18)]

"That the demand for grant on Account under the head fisheries be reduced by Rs. 100"

[Failure in providing jobs to the trained youth in fisheries industry in District East Champaran. (19)]

"That the demand for grant On Account under the head Industries be reduced by Rs. 100"

[Failure to develop small scale industries in District East Champaran of Bihar. (20)].

SHRI KAMLA MISHRA MADHUKAR (Motihari) : I be to move :

"That the demand for a Supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 52,17,000 in respect of Council of Ministers, Election, Secretariat and District Administration be reduced by Rs. 100"

[Failure to check large scale bribery prevalent in the Administration of Motihari and other places. (1)].

"That the demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 52,17,000 in respect of Council of Ministers, Election, Secretariat and District Administration be reduced by Rs. 100"

[Failure to check corruption rampant at block level. (2)].

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 52,17,000 in respect of Council of Ministers, Election, Secretariat and District Administration be reduced by Rs. 100',

[Failure to check bungling of lakhs of rupees committed by B.D.O. of Madhuban Block of East Champaran District. (3)]

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs.26,40,000 in, respect of Administration of justice and other Social and Community Sevices be reduced by Rs. 100"

[Failure of the Department of justice to dispose of thousands of pending cases of share croppers in Bihar. (4)]

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 26,40,000 in respect of Adminis-

stration of justice and othe Social and Community services be reduced by Rs. 100"

[Difficulties being faced by the poor as a result of late disposal of thousands of cases in Bihar. (5)]

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 26,40,000 in respect of Administ ation of justice and other Social and Community services be reduced by Rs. 100"

[Failure to provide adequate legal assistance to landless persons. (6)]

"That the demand for a Supplementary Grant of sum not exceeding Rs. 1,61,26,000 in respect of Land Review and Relief on account of natural calamities be reduced by Rs. 100"

[Failure to implement land ceiling laws in East Champaran District. (7)]

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,61,26,000 in respect of Land Revenue and Relief on account of Natural Calamities be reduced by Rs. 100"

Failure to provide timely relief to people affcted by natural calamites in 'Madhuban, Pakasi Dayal, Harisidhi and many other Anchals. (8)]

"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 6,17,93,760 in respect of Police, fire Protection and Control and other administrative services be reduced by Rs. 100"

[Failure to check anti-people acts of police personnel of Pipra Ramgarhwa, Raksaul and Kharuria Police Stations in East Champuran District. (9)]

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 6,17,93,76 in respect of Police, Fire Protection and Control and other Administrative Services be reduced by Rs. 100"

[Failure to check bribery prevalent in most of the Police Stations of East Champaran. (10)].

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum is not exceading Rs. 6,17,93,760 in respect of Police, Fire Protection and Control and Other Administrative Services be reduced by Rs. 100"

[Failure to bring any improvement in Police Administration after Independence . (11)]

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,79,145 in respect of Education and Art and Culture be reduced by Rs. 100."

[Failure to provide jobs to the trained teachers of District East Champaran (12)].

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,79,145 in respect of Education and Art and Culture be reduced by Rs. 100"

[Failure to set up an Agricultural College at Piprakothi in District East Champaran . (13)]

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 55, 79,210 in respect of Health and Family Welfare by reeduced by Rs. 100"

[Scarcity of medicines in the Sagri Hospital in District East Champaran. (14)].

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 55,79,210 in respect of Health and Family Welfare be reduced by Rs. 100."

[Failure in increasing beds in Government Hospital at Varachatria in District East Champaran. (15)].

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 6,79,68,035 be reduced by Rs. 100".

[Wide spread corruption in the office of Civil Surgeon in Mothihari Sadar Hospital in District East Champaran. (16)]

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 6,79,68,035 be reduced by Rs. 100".

[Delay in the expension of Government Hospital at Ameraji in District East Champaran. (17)].

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 6,79,68,035 be reduced by Rs. 100"

[Failure to clean Motihari lake in order to make it worthy for public use. (18)].

[Shri Kamla Mishra Madhukar]

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs 6,79,68,035 be reduced by Rs. 100".

[Failure to make arrangements for water supply in Varachatria. (19)].

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 6,79,68,035 be reduced by Rs. 100"

[Delay in the implementation of wate supply scheme in Kesaria (20)].

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 6,79,68,035 by reduced Rs. 100"

[Failure to develop land for Harijans at Chandi, Areraji, Kesaria etc. in East Champaran. (21)].

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 20 in respect of Labour and Employment be reduced by Rs. 100"

[Failure to provide jobs to the educated unemployed of Bihar. (22)].

"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 20 in respect of Labour and Employment be reduced by Rs. 100"

[Failure to provide unemployment allowance to the uneducated unemployed of Bihar. (23)].

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में बिहार के बजट के प्रश्न को लेकर जो चर्चा और विवाद चल रहा है और बिहार की गरीबी, बिहार की बेकारी और बिहार मे फैली हुई बद-अमनी की चर्चा की गई है, इससे पहले कि मैं इन प्रश्नों पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूं, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि यह बात आज ठीक है कि देश में बिहार की स्थिति सबसे दुःखद है—चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो—लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन और इस देश के नेताओं को यह बताना चाहता हूं कि बिहार राज्य भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका एक विशेष स्थान है । आदिकाल से जब से भारत का इतिहास मिलता है, इतिहास के हर मोड़ पर बिहार ने भारत का मार्गदर्शन किया है । भगवान गौतम बुद्ध के समय में शायद भारत की ऐसी स्थिति रही होगी जिसके कारण भगवान बुद्ध ने इंकलाब का झण्डा, कामनवैल्थ का झण्डा बिहार में गाड़ा था ।[1] यहीं तीर्थंकर महावीर जैन हुए, जिसने सम्पूर्ण भारत को मार्ग दिखाया । जब बिहार के समाज पर संकट आया तो अशोक ने भारत को एक नई दिशा दी, जब हिन्दुस्तान गुलामी के संकट पर था तब उसी बिहार के चन्द्र गुप्त ने सैल्यूकस को हराया । जब मुगलों का राज्य था, तब बिहार ने ही एक ऐसा शासक पैदा किया—शेरशाह, जिसने ढाका से लाहौर तक चार लेन में सड़क बनाई और सारे एडमिनिस्ट्रेशन के डवेलपमेंट की नींव की बुनियाद डाली । जब अंग्रेजों का राज्य हुआ तो कुंवर सिंह जी पैदा हुए और जब हिन्दुस्तान अंग्रेजों के वर्चस्व में फंस गया तो महात्मा गांधी को भी रोशनी चम्पारण में मिली और जब भारत आजाद हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति, इस राष्ट्र का देशरत्न, डा० राजेन्द्र प्रसाद, बिहार ने ही दिया । इसलिए सीता से ले कर डा० राजेन्द्र प्रसाद तक भारत की जनता की बिहार ने जो सेवा की है, वह इतिहास में लिखी हुई है । आज यदि बिहार गिर गया है, बिहार दलित हो गया है, बैकवर्ड हो गया है, तो फिर सम्पूर्ण राष्ट्र का यह कर्त्तव्य है कि वह सहानुभूति के साथ, आदर के साथ बिहार के उत्थान में अपना योगदान दें । मैं इस सदन से बिहार के प्रति हमदर्दी, सहानुभूति और सहयोग की अपेक्षा की भावना को लेकर खड़ा हुआ हूं ।

जैसा मैंने शुरु में अर्ज किया, निवेदन किया , कि आज की परिस्थिति हमें विरासत में मिली है । जिस बिहार ने जातीयता पर सबसे बड़ी चोट की और जिस बिहार ने गांधी जी को ज्ञान दिया और गांधी जी ने इस देश से साम्प्रदायिकता को मिटाने के लिए अपना बलिदान दिया, उसी बिहार को इस ढाई वर्ष के दौरान कास्टिज्म और कम्यूनलिज्म की लैबोरेट्री बनाया । मैं यहां किसी पर आक्षेप नहीं करता हूं । चौधरी चरण सिंह और उनके शिष्य कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में जातीयता का वह बीज बपन किया कि ग्राम पंचायतों में जो चुनाव हुए , तो उनके शब्दों में :

" बता इच भर ठौर कहां वह,
जिस पर शोणित बहा न मेरा ।"

गांव-गांव मे, घर-घर में, बन्दूक, गोली, लाठी , एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ, एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ खून का प्यासा हो गया है । अशोक भूमि में, बुद्ध की भूमि में, गांधीजी की भूमि डा० राजेन्द्र प्रसाद हुए और उसी दल का एक हिस्सा, उसी जनता पार्टी का एक हिस्सा है—आर० एस० एस० इण्डिया का सब से सैन्सेटिव लेबर एरिया, जमशेदपुर डेढ़ महीने तक साम्प्रदायिकता के कारण सारा काम छोड़ कर बैठा रहा—यह हमारी रियासत है ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ इस चीज को ले कर आप जानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में जातीयता और साम्प्रदायिकता गांव-गांव में फैली हुई है और आर्थिक क्षेत्र में जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से आर० एस० एस० और जनसंघ के ब्लैक-मार्केटीयर्स, मुनाफाखोरों ने जन वितरण प्रणाली के माध्यम से दुकानों का जाल बिछा दिया । हमारे बिहार में बहुत मशहूर है—यह जनसंघ कौन पार्टी है—"बोलो बम, तोलो कम" । ये गांव के बच्चे बोलते हैं और सारी दुकानों पर यही इकोनोमिक सिस्टम इन्होंने इजाद किया । सामाजिक क्षेत्र में लोक दल ने जातीयता, साम्प्रदायिकता और आर्थिक क्षेत्र में आर-एस-एस व "बोलो बम तोलो कम" ब्लैक-

मार्केटियर बनों— इस तरह का प्रचार किया। ये दोनों मिल कर इस तरह का हैवक बिहार में फैला रहे हैं। ये आज बिहार के लिए प्राबलम नं० 1 है। जब बैलेट-पेपर पर हार गये तो इन्होंने इस तरह के काम शुरू कर दिये हैं। इन्होंने सोचा था कि कांग्रेस पार्टी को केवल 4 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस-आई वालों की जमानतें जब्त होंगी और पटियाला से लेकर पटना तक अपना एकछत्र साम्राज्य हो जायगा। लेकिन केवल 5 सीटें बिहार में जीत कर रह गये, वहां की जनता ने कास्टीज्म को, कम्यूनलिज्म को रिजेक्ट कर दिया और हम 30 सीटों पर जीते। जब ये बैलट में हार गये, साम्प्रदायिक युद्ध में हार गये, धर्म युद्ध में हार गये, न्याय युद्ध में हार गये, तब फिर अन्याय-युद्ध पर आ गये। कैसा अन्याय युद्ध कर रहे हैं —गांव-गांव में जातीयता को बढ़ावा दे कर—"अबल जानि श का सब काहू" अबलजनता को मारने का प्रयास कर रहे हैं। इन जातीयता की आग सुलगाने वालों ने जो स्थिति वहां पर पैदा की उस में कमजोर वर्ग के लोगों, हरिजन लोगों को ज्यादा मारा गया जब इस बात को यहां पर कहा जाता है तो वे लोग तिलमिला उठते हैं। यह सब पोलिटीकल मूव है। मैं इस बात से डिस-एग्री करता हूं जो यह कहते हैं कि यह इकानामिक मूव है। यह इकानामिक मूव नहीं है, जब तक असेम्बली का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक जातीयता के यज्ञ में ये आहुतियां होती रहेंगी। उन का नारा है कि जातीयता को बरकरार रखो, कास्टीज्म को कायम रखो क्यों कि इन के पास कास्टीज्म के सिवा कोई पूंजी नहीं है। इस लिए यह एक टेम्परेरी पोलिटीकल मूव है— to keep alive the tissues of casteism and communalism in the State of Bihar so that they can face the elections with this twin weapon

हमारे यहां हर चीज की स्केअरसिटी है, लेकिन वास्तव में नहीं है। चीनी की कमी नहीं है, डीजल की कमी थोड़ी-बहुत है, लेकिन जितना हाहाकार मचा हुआ है, उतनी कमी नहीं है। जितने स्मगलर्स हैं, ब्लैक मार्केटियर्स है, वे लोग जन-वितरण प्रणाली में घुस गये है। एक तो करेला और दूसरे नीम चढ़ा। पिछले ढाई साल के एडमिनिस्ट्रेशन में हालात इतने खराब हो गये हैं, कि जो रिजेक्टेड डिजेक्टेड, कण्डेम्ड आफिसर्ज थे, उन को हर महत्वपूर्ण जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। आप 5 रुपया ले कर जाइये, डीजल ले लीजिए और इस भाव में जितना चाहे उतना ले लीजिए। 6 रुपया किलो में चीनी ले लीजिए। डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन पम्प पर डीजल नहीं है। लारी से आ रहा है, दिखला दिया कि लारी ओवर-टर्न हो गई, लुट गई। सहरसा में तीन-तीन डीजल की लारियों को शो कर दिया गया कि लुट गई। इस लिये यदि इस सरकार को अभी भी समय रहते भंग न कर दिया जाता, तब फिर तो बिहार का भगवान ही मालिक था।

अब बिहार में चुनाव होने वाला है—वहां पर हम सरकार बनाने वाले नहीं हैं, बिहार की जनता सरकार बनाने वाली है। हम जनता को फेस करने से नहीं डरते हैं, हम ने पहले भी चुनाव कराया है और आज भी कराने को तैयार हैं, बल्कि चुनाव में जाने को तैयार हैं। जब तक बिहार में चुनाव नहीं होता है, यह बजट तभी तक के लिए है। हम तो वहां पर एक काम-चलाऊ सरकार चला रहे है और इसी सन्दर्भ में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन चार महीनों के अन्दर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब-डिवीजनल लेवल और ब्लाक लेवर पर पीपुल्स रिप्रेजेण्टेटिव्ज को, हर वर्क्स-आफ-लाइफ के लोगों को लेकर, रेस्पेक्टेड सिटिजन्स को ले कर जो ला-एण्ड-आर्डर की समस्या है, जो जन-वितरण प्रणाली की धांधली है उस को रोकने की आवश्यकता है। ताकि आफिसर, सरकार और जन प्रतिनिधि कन्धे से कन्धा मिला कर जो एबयूट प्राब्लम्स हैं, उन को फेस करें और वहां के लोगों को थोड़ी बहुत राहत यह सरकार दिलवे।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार से हर गांव के ग्रामीण रात भर जागते हैं और दिन को काम की तलाश में भागा करते हैं। हम ने पिछले चुनावों में उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि ज्यों ही हमारा शासन आएगा, तुम्हारी सोने की रातें वापस मिल जाएंगी, सड़कों पर जो उठाईगिरी और गुण्डागर्दी होती थी, वह समाप्त हो जाएगी और जो भूख से मरते हो, उसके लिए जो सामान पहले 8 रुपये किलो मिलता था और वह 14 रुपये मिलने लगा था, वह फिर उसी कीमत पर आ जाएगा। इसलिए इस लोक सभा चुनाव में जनता ने जो हमें वोट दिया है, वह इन्हीं दो प्रमुख मुद्दों पर वोट दिया है, एक तो उसे सोने की रात वापस मिल जाएगी और दूसरे यह जो आकाश को चूमती हुई कीमतें हैं, ये उन की जेबों के पैसों के बराबर आ कर संधि कर लेंगी। पहले यह सम्भव नहीं था क्योंकि विभिन्न प्रान्तों में दूसरी सरकारें थीं और वे ऐसा करने में सफल नहीं होती। मैं उन पर और कोई इल्जाम तो नहीं लगाता, क्योंकि उस के लगाने के लिए तो और समय मिलेगा लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर पाई, तो उनको भंग कर दिया गया और अब भंग करने के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन है। प्रसन्नता की बात है कि वहां पर राज्यपाल महोदय वही है, जो जनता पार्टी के राज्य में नियुक्त हुए थे, जिन पर संभवत अब उन को विश्वास है या नहीं मुझे नहीं मालूम लेकिन हम लोगों को विश्वास है और हम यह चाहते हैं कि बिहार के प्रशासन में सुधार हो। हम एसेम्बली के चुनाव तक प्रतीक्षा न करें बल्कि दो महीनों में ही, मई में जब भी चुनाव हो, उस के पहले ही बिहार के प्रशासन में सुधार किया जाए। आज बिहार में वही राज्यपाल हैं और उन के एडवाइजर है लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार के 30 जिलों के कलक्टर, एस०पी० को भी नहीं जानते, तो वे शासन नहीं चला सके। बिहार के अन्दर 30 जिले हैं और मेरा कहना यह है कि उन में ऐसे कलक्टर जाएं, ऐसे एस०पी० जाएं, जो योग्य हों और जिन को जनता से प्रेम हो। सब से प्रमुख बात आज बिहार के लिए यह है कि इन 30 जिलों में ऐसे प्रशासक जाएं, जो बिहार की जनता से प्रेम करें

[श्री भागवत झा आजाद]

हों, जिनको अपनी जेब से प्रेम न हो । मैं ऐसे कलक्टर को जानता हूं, ऐसे एस०पी० को जानता हूं, जिसके दिमाग के अन्दर कुछ नहीं है सिवाय भूसे के । गैलरी में बैठे हुए अधिकारी मुझे ऐसा कहने के लिए क्षमा करेंगे लेकिन मैं यह जानता हूं कि उनके पास कोई अकल नहीं है और मैं ऐसे एस०पी० को भी जानता हूं जिस के पास कुछ अकल तो है लेकिन काम करने के लिए नहीं है बल्कि आई० पी० एस० की बड़ी डिग्री ले कर पैसा जमा करने की अकल उस में है । इस तरह के लोग कैसे यह राज्य चलाएंगे । बिहार एक तरफ तो अड्डा है, एक जाति के मेहन्त और मठाधीश बैठे हुए है । मैं चाहता हूं कि यह भारत सरकार हमारे प्रधान मंत्री, बिहार के राज्यपाल उन मठाधीशों को, जो अपने को बड़ा योग्य और काबिल समझते है, वहां से हटा कर दिल्ली भेज दें और दिल्ली के अन्दर आ कर वे, काम करें । दो महीने के अन्दर ही उन की अपनी योग्यता का पता चल जाएगा । उन्होने बिहार पर बड़ा अहसान किया है, हम पर बड़ी कृपा की है । अब उन को वहां से भेजा जाए । चुने चुनाए कोई स्पेशल कमिश्नर है, कोई डिप्टी कमिश्नर है और कोई विशेषाधिकारी है । कोई अमुक महन्त हैं और कोई फलां मठाधीश हैं, जिन्होंने 30 लाख रुपया प्रोमोशन देने के लिए और समूची लिस्ट में गड़बड़ कर के कमाल कर दिया । तमाम लोगों की उपेक्षा करके सुपरसीड कर के कैसे कैसे व्यक्ति को चीफ़ इंजीनियर, मुख्य अभियन्ता बना दिया । ऐसे लोगों का आप दिल्ली में प्रोमोशन कर दीजिए और दूसरी बात यह है कि बिहार के सम्पूर्ण जिलों मे ऐसे व्यक्ति भेजे जाएं, जिनके पास अकल हों और जिन के मन में पिपरा गाव के हरिजनों के प्रति सहानुभूति हो । नही मालूम था बिहार के उन अधिकारियों को पिपरा गांव के आसपास मीटिंग हो रही है बड़े बड़े जमींदारों की और इस तरह से हरिजनों पर चढ़ाई की योजना बनाई जा रही है ? उनको क्या यह मालूम नही था कि वहां पर चन्दे लिये जा रहे हैं ? बेचारे दूध के धोये थे, जो ये सब चीजें उन को मालूम नहीं थीं भागलपुर, पटना के कमिश्नर और दूसरे अफसरों को इस के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि पिपरा में क्या होने जा रहा है । जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है, तब ऐसी ही स्थिति होती है । पिपरा गांव के बाहर, जहां 9 हरिजनों को मारा गया है, एक कुतिया भी मरी पड़ी हुई पाई गई थी । उन ने भौंक भौंक कर उन बदमाशों को रोका था । लेकिन गोली खा कर या लाठी खा कर मर गयी । संभवत: वह चित्रसेन की चित्रांगना होगी । चित्रसेन के महल के बगल में एक झोंपड़ी थी । उसमें एक बुढ़िया रहती थी और उसमें रहती थी उसकी षोडशी रूपवती लड़की । एक दिन चित्रसेन महाराज उस झोंपड़ी में मेहमान बन कर गए । चित्रांगना भोंकने लगी । इस पर बुढ़िया ने बाहर आकर कहा कि क्यों भोंकती हो ? तुम्हारे भोंकने से क्या होगा । जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो तुम्हारे और मेरे भोंकनें से क्या होगा । इतना सुन कर चित्रांगना चुप हो गयी । इस चित्रांगना को तो वह बुढ़िया कह भी नहीं पायी क्योंकि संगिनधारियों की संगीनें पहले ही बाहर हो गयी थीं ।

14.00 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की समस्याओं का प्रमुख कारण वहां का प्रशासन है और साथ साथ बिहार का राजनीतिक नेतृत्व भी । उत्तर भारत में आर्यवर्त की भूमि गंगा और यमुना के किनारे उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान एक हाथ हल पर और एक हाथ तलवार पर रख कर लड़े और गोलन दर्रे और खैबरपास से आने वाले आततायियों का सामना किया । लेकिन उस के बाद आने वाले अंग्रेजों के खिलाफ जब 1857 और 1921 की क्रांतियां हुई जिनके बारे में मेरे मित्र कमल नाथ ने बहुत-सी बातें याद दिलायीं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम उनके बेटे, उनके उत्तराधिकारी जो हम हिन्दुस्तान में रहते हैं, इन बातों को भुल गये । इसीलिए हमारी दुर्गति हुई । हमारे स्वयं के कारण से भी हमारी दुर्गति हुई ।

आज बिहार को आवश्यकता है राजनीतिक नेतृत्व की । वह व्यक्ति कौन है जिस पर बिहार की तमाम जनता का विश्वास हो ? यह हमारा नारा है । ऐसा कौन व्यक्ति है जो अगले चुनाव के बाद बिहार को नेतृत्व दे ? उस के बाद 22 ईमानदार मंत्री बिहार को मिलेंगे, 22 स्पेशल सेक्रेट्री बिहार को मिलेंगे । बिहार में प्रशासन का सुधार अति आवश्यक है । अगर यह नही हुआ तो वही बिजली बोर्ड जिसकी कल्पना अभी आपने की । बिजली बोर्ड बिहार की एक सुन्दर जमीदारी है । जो चाहे आ कर के अपने अपने बड़े घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दे और चरने वाले जब चर लें तो फिर वापस अपने स्थान पर चल जाए और अपने मालिक को खुश कर दे । बिजली बिहार के लिए आवश्यक है । क्या वजह है कि आज 600 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्शन के बाद भी 200 मेगावाट बिजली मिलती है ? क्योंकि उन बिजली बोर्डों मे ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाता है जो सिर्फ चरने और खाने के लिए वहां जाते हैं ।

मुझे क्षमा करें हमारे अधिकारीगण । हमारे अधिकारीगण भी कम राजनीतिज्ञ नही हैं । बदनाम तो हम राजनीतिज्ञों को किया जाता है लेकिन चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे बिहार के अन्य आफिसर्स हों, राजनीति में हम उनसे बहुत कम हैं । हम उन को भ्रष्ट मानते हैं और अपने को सेकिंड मानते हैं । लेकिन बदनामी तो हम को लगी है । मैं कहता हूं कि इन राजनीतिज्ञ प्रशासकों को बिहार प्रशासन से बाहर दिल्ली भेजिये, ताकि वे इस महान् नगरी में, इस देश के महान् शासन में अपनी अकल और बुद्धि का परिचय दें । बिहार के राज्यपाल और हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री को सब से पहले यह काम करना चाहिए । दूसरे इन चुनावों के पूर्व तमाम जिलों में परिवर्तन करना चाहिए । जो कलेक्टर, एस०पी० चंदा ले कर पैसा इकट्ठा करते है और किसी खास पार्टी के किसी उम्मीदवार को जिताने के लिए उसे देते हैं, उन्हें तो हटाना ही नहीं चाहिए बल्कि उन्हें तो डिसमिस करना चाहिए । इन्हें पहचानो—

आई०ए०एस०, आई०पी०एस० हैं,
कहते अपने को प्रजातंत्र के वाचडोग,

कोटि-कोटि जनता के भाग्य विधाता हैं वे,
पूछो इन से तेरी किस्मत कहां, किधर,
किन फाइलों में,
कैद किये रख छोड़ा है ?

जब तक इन फीतों से, इन फाइलों से हमारे बिहार के राजनीतिक नेता वहां की जनता को नहीं छुटा पायेंगे तब तक बिजली बोर्ड नहीं सुधरेगा । जब तक हमारे क्षेत्र भागलपुर में गंगा का ब्रिज नहीं बनेगा तब तक हम पावर स्टेशन भी नही बना पायेंगे । कमाल की बात है । वाह रे बिहार के नेता, शासक, प्रशासक । भागलपुर के पास मिलियन मिलियन टंस कोयला निकला है, भागलपुर के पास कहलगांव में गंगा का पानी है लेकिन सुपर पावर स्टेशन बिहार में नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा । मैं प्रांत की बात नहीं कहता, अगर आपके प्रांत में, आपके क्षेत्र में, जस्ता, कोपर मिलता है तो आवश्यक है कि जस्ते का कारखाना वहीं लगाया जाना चाहिए, उसके बाहर नही । लेकिन आज लालमटिया का कोयला ताम्बा रेलवे लाइन बना कर के ले जाया जाएगा दूसरे स्थानों में तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी तो सदन में नही इस वास्ते मैं वित्त मंत्री जी को कह देना चाहता हूं कि लालमटिया का कोयला तब तक सुपर थर्मल स्टेशन के लिए जाने नही दिया जाएगा मेरे क्षेत्र से और तब तक उस रेलवे लाइन को भी बनने नहीं दिया जाएगा और तब तक वहा पर भूमि का अर्जन नहीं होने दिया जाएगा जब तक हमारी आवश्यकताओं के अनुसार कहलगांव में थर्मल स्टेशन बना नही दिया जाता है । मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि हर प्रान्त की, हर प्रान्त में भी हर क्षेत्र की और हर क्षेत्र में भी उस के आसपास की जनता ने अपनी शक्ति को आज पहचान लिया है । लालमटिया का कोयला रेलवे लाइन बना कर के नही जाने दिया जाएगा यह मैं साफ कह देना चाहता हूं । बिहार में प्रशासन का सुधार होना भी बहुत जरूरी है । पहले ऊपर के स्तर पर और उसके बाद नीचे गांव तक के स्तर पर यह सुधार होना चाहिये । साथ ही कहलगांव में थर्मल स्टेशन देने के लिए भागलपुर में गंगा पर पुल बनाने की आवश्यकता हो तो उसको बनाया जाना चाहिये, जहां पर डबल लाइन की आवश्यकता हो, वहां वह बनाई जानी चाहिए और जहां जहां पर बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाओं की आवश्यकता हो, वहां वहां पर उनको भी बनाया जाना चाहिये । वर्मा जी ने कहा कि बिहार की भूमि प्यासी है । ठीक बात है वह प्यासी है । वह इसलिए प्यासी है कि हम ने सैंकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके कुसुमघाटी जलागार बनाया लेकिन वहां की बदनसीबी को आप देखें, वहां की बदनीयती को आप देखें, वहां के मिसमैनेजमेंट को आप देखें कि आज उससे पानी उन क्षेत्रों को नहीं मिलता है जो उसके अधिकारी हैं लेकिन टैक्स का भार उन पर डाल दिया जाता है जिन्होंने उस पानी का उपयोग ही नहीं किया होता है । इस तरह की शासन व्यवस्था आज बिहार में है । इस में सुधार लाया जाना चाहिये ।

मैं अपने सम्पूर्ण क्रान्ति के नारे लगाने वाले मित्रों से कहना चाहता हूं कि मैं उनका विरोध नहीं करता हूं । सम्पूर्ण क्रान्ति देश को चाहिये थी । जो अधिकार जनता के हैं वे उनको मिलने चाहिये । शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता को सभी महसूस करते हैं, सभी उसके बारे में बोलते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री सभी कहते हैं कि उस में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये । लेकिन आप देखें कि 1967 में जो शिक्षा के सम्बन्ध में व्हाइट पेपर इस लोक सभा में रखा गया था उसको कार्यान्वित नही किया गया है । ऐसी अवस्था में अगर बिहार का बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आता है तो जुल्म क्या करता है । सम्पूर्ण दक्षिण बिहार में बनी प्राजैक्टों में लेबर मिनिस्टरी के आदेशों के अनुसार कि तीन सौ रुपये तक की नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिये, अगर उनको नही दी जाती हैं और उसको ले कर अगर विद्यार्थी विद्रोह करते हैं तो इस में उनका क्या दोष है, ऐसी अवस्था में विद्यार्थी विद्रोह न करें तो क्या करें । आपका मुंह देखकर वे कब तक इंतजार करते रह सकते हैं ।

यह स्पष्ट बात है कि सम्पूर्ण क्रान्ति वाली बात सफल नही हुई है । इसका कारण यह है कि उसका नेतृत्व कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए किया ।

Men invented plans and apes got hold of them.

बिहार में यही हुआ है । फिर यह गलती नही दोहराई जानी चाहिये । वहां के नौजवान, वहां के विद्यार्थी ऐसी शिक्षा मांगते हैं जो उन्हें नौकरी दे, बेरोजगार नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो कर काम कर सकें, अपने साधनों से वे फैक्ट्री वहां पर बनाते हैं या आप वहां पर कोई फैक्ट्री बनाते है या कोई और फैक्ट्री वहां पर लगती है और उस में वे रोजगार मांगते हैं तो उनका क्या दोष है । अगर यह चीज सम्भव नहीं हुई और ऐसा हुआ नहीं तो सम्पूर्ण क्रान्ति किसी और रूप में आएगी । मैं खूनी क्रान्ति का समर्थक नहीं हूं । लेकिन मैं उनको नक्सलपन्थी नही मानता हूं । एक सेर अनाज उस मजदूरी के लिए जो वे वहां पर करते हैं उसको ले कर किसी ने जाकर समझाया कि वे इस शोषण के खिलाफ अपने अधिकारो के लिए लड़ें और ऐसे लोगों को अगर आप नक्सलपन्थी कहते हैं तो हम भी नक्सलपन्थी होना मंजूर करेंगे । यह निषिद्ध नहीं है । उस प्रदेश की भूखी नंगी जनता को बचाने के लिए जो आज उड़ीसा से भी नीचे नम्बर पर आ गई है, शासन को चाहिये कि वह तुरन्त कार्रवाई करे ।

समय शेष है नहीं पाप का है अपराधी व्याध
जो तटस्थ है, जो पदस्थ है, समय गिनेगा उनका भी अपराध ।

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA (Aurangabad) : While speaking on the Budget, may friend Shri Shri Kedar Pandey referred to the action of the Union Government in dissolving Bihar Assembly and along with it eight others. He justified the action on the ground that the law and order

[Shri Satyendra Narayan Sinha]

situation in Bihar was deteriorating and, therefore, development work had suffered completely.

I wanted to tell him that this is not the ground given by the Union Law Minister. He has said that the State Governments were delaying the ratification of the Constitution Amendment, that the State Governments were not carrying out the directives for implementation of progressive laws and that the Governments have forefeited the confidence of the people. These were the three reasons given by him. But I dare say that these reasons do not apply to Bihar at all. Even with regard to the point that Mr. Kedar Pandey made out, I would like to remaind him with a gratitude that it was the Congress (I) which had helped the Janata Ministry to tide over the crisis that it faced after the split in the Janata Party. But then they changed their mind and when all the opposition parties rallied round this Government, they thought it fit to dissolve the Assembly. It is all the more amazing that the Bihar Assembly was in session when the Central Government intervened and dissolved the Assembly and dismissed the Ministry. This is unprecedented. I do not think the famers of the Constitution ever intended that such action could be taken.

AN HON. MEMBER : When the Janata Government dissolved the Assemblies, was it not unprecedented?

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA : He did not hear me. I said, it was, unprecedented in the sense that never has the Union Government intervened when the Assembly was in session. They have always said that the Government was not being carried on in accordance with the provisions of the Constitution and they have not carried out the directives of the Centre. In this particular instance, no directive had been issued . The State Government had assured the Centre that they were going to take up the ratification of the Constitution Amendment during this session. Then where was the question of defiance?

With regard to the law and order situation, my friend said that it had deteriorated. True, there were some instances for which we are sorry. But I believe Mr. Pandey would recall that as soon as the incidents in Parasbigha and Dohia took place, the State Government acted with promptness and effectiveness. They transferred the entire administrative personnel down to the sub-inspector of police, where as in the case of Pipra you have not done it. As my friend, Shri Bhagwat Jha Azad said, is it not a lapse on the part of the administration that when meetings were being organised and tension was building up, yet they did not take preventive action and they allowed this carnage to take place ? Whose fault is it ? You have not taken any action against the administrative personnel. You have not entrusted the investigation to the crime branch, where as in the case of Parasbigha and Dohia, we have entrusted the investigation to the crime branch and took action against those officers. We have appointed enquiry committee under the chairmanship of a senior member of the Board of Revenue to report about the lapses of the administrative personnel, so that the State Government could take action against them. These you have not done. I agree that you send Union Home Minister there. But so far as the administration is concerned, the administration had failed. It was incumbent on you to have taken action against those people, which you did not do. I entirely agree with Shri Bhagwat Jha Azad that those people should have been taken to task. I was referring to the dissolution. There cannot be any justification for this action. The farmers of the Constitution never intended this. The last point that the Law Minister has made that the Ministry had forfeited the confidence of the people, does not hold good in this case. Look at the judgement of the Supreme Court. What has Mr Justice M. Fazal Ali said about it ? He has narrated the incidents—how the emergency was imposed, how the excesses were committed. What was peculiar at that time was that the main thrust of the election propaganda was democracy vs dictatorship. People voted against dictatorship. In several of the States not a single representative of the Congress was elected. In this case of Bihar, the Congress Party has secured only 36 per cent of the votes. Since the election system is such that on a minority vote you can get majority of the members elected, you cannot say that the party in power has completed, for feited the confidence of the people, particularly, when the entire opposition rallied behind the Government. So, the reasons given by the Law Minister do not apply to Bihar. This action of the Central Government was taken purely and patently on narrow partisan political considerations. Therefore the apprehension of the threat to the federal policy becomes more genunine and real.

The Budget of the Bihar Government is before us. But the Government in Bihar is in the nature of a care-taker Government since the elections are to take place in May. Therefore, we do not expect the Government to take any major policy decision. So, I would not make any submission on that point. I would only submit that Bihar has suffered badly due to drought and many parts of the State are still under drought conditions. Therefore, I plead

with the Centre to give liberal assistance to the State Government to meet the needs of the situation.

I agree with Mr. Bhagwat Jha Azad that this Government should start streamlining the administration if they want to do real good to the people.

Let me invite the attention of the Government to some of the routine problems of the State. The State Government introduced the public distribution system on Ist July, 1979 and opened 30,150 fair price shops. For the March month, the requirement of the State is 2.35 lakh tonnes of foodgrains. This requires 90 rakes of goods trains for reaching the supply to Bihar for the month of March. But what is the position? We require three rakes per day and against this requirement we are getting 1.1/2 or 1.3/4 rakes per day. This was the position upto 12th March 1980. This has to be remedied.

Coming to sugar, consequent upon the imposition of partial control on sugar in December 1979, the FCI is entrusted with the task of procuring and supplying sugar to fair price shops at the rate of 875 grammes per head in urban areas and 356 grammes per head in rural areas. The quantity allotted to Bihar is far less than the requirements. Our real difficulty is poor despatch. For instance, no despatch could be made against the February quota of 16,000 tonnes from the Maharashtra factories. Similarly, against an allocation of 5,855 tonnes of sugar from U.P. factories against the December-January quota, only 1,464 tonnes could be despatched and only 600 tonnes could be received. Even from the Bihar sugar factories the FCI lifted only 2,700 tonnes against the December-January quota of 12,814 tonnes and 2,777 tonnes against the February quota a of 11,000 tonnes.

Coming to kerosene, the total requirement of Bihar is 30,000 tonnes per month. There is a significant gap between the requirements and allocation.

In the case of diesel, the State Government asked for 70,000 tonnes of diesel per month in view of the severe drought conditions and the too frequent failure of supply of electricity. But the Government have allotted only 36,000 tonnes for March and the actual receipt is far less than even this allocation.

So far as drinking water supply is concerned, I am glad that the State Government has made efforts to augment it. It has placed an order for 29 rigs with the DGS&D. There is slackness in executing this order.

The State Government had already passed orders with regard to conversion of constituent colleges. But the Governor has stayed those orders for review. I would submit that the Government must expedite the notification regarding the constituent colleges, because the teachers in Bihar have been agitating for converting these colleges into constituent colleges.

Bihar has suffered very severe drought conditions. So, the agriculturists require loans for carrying on their agricultural operations and for meeting even their food requirements. The State Government has allotted Rs. 25,000 per block. This is very very inadequate. It should be increased to at least Rs. 1 lakh per block so that the urgent requirements of the people could be met.

I conclude with the hope that the suggestions that I have made with regard to suggar, diesel and kerosene would be accepted.

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की आबादी करीब 6 करोड़ है और उस 6 करोड़ में करीब 14 फीसदी मुसलमान हैं। बिहार एक ऐसा सूबा है जहां पर हमारे बुजुर्गों ने जन्म लिया है। लार्ड बुद्ध वहीं के थे, हजरत शहबाज रहमतुल्लाह अले साहब वहीं के थे, हजरत मखदूम रहमतुल्लाह साहब वहीं के थे, गुरु गोविन्द सिंह साहब वहीं के थे। महात्मा गांधी ने जो अपना आन्दोलन शुरू किया वह भी वहीं से किया और भारत ने अपना पहला सदर जो दिया वह भी बिहार से थे। मौलान मजहरुल हक साहब वहीं के थे। बहुत जद्दोजहद के बाद जब आजादी आई और हमारी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई तो हम लोगों ने एक रास्ता अख्त्यार किया अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक और काम आगे बढ़ा। जिस के लिए हम लोग कमिटेड थे हमने उस काम को आगे बढ़ाया। इसी तरीके से 1971 में लोगों ने एक भारी बहुमत से, काफी तादाद में हम लोगों को अपना मत देकर लोकसभा में भेजा था और हम लोगों ने अपनी पार्टी के प्रोग्राम के मुताबिक काम को शुरू किया था। चूंकि हमारी पार्टी को भारी बहुमत मिला था इसलिए यह बात दूसरी हमारी पार्टीज के लोगों को बहुत खली। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जब हमारी पार्टी अपने सोशल और एकोनामिक प्रोग्राम के ऊपर अमल कर रही थी उसी बीच में एक षड़यन्त्र रचा गया और उससे देश में ऐसी हवा फैलाई गई, ऐसे हालात पैदा किये गए कि एकोनामिक और सोशल फील्ड में एक जमूद आ गई। उसके नतीजे के तौर पर यह हुआ कि जो काम हम शुरू कर रहे थे या शुरू कर चुके थे अपनी पार्टी की लीडर श्रीमती इन्दिरा गांधी की रहनुमाई में उसमें हर बात पर दखलअन्दाजी की गई। मुल्क में नफरत की ऐसी फ़िजा तैयार की गई कि जो अवामी नुमाइन्दा चुनकर आये थे उनसे मार-पीट शुरु हो गई और दंगे-फसाद शुरू हो गए। सारे बिहर में ऐसी फिजा पैदा की गई कि दंगे-फसाद शुरू हो गए।
(व्यवधान) जमशेदपुर में आपका साथी हमारी जनता

[श्री जमीलुर्रहमान]

पार्टी) दीनानाथ पांडे गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि मौलाना कादरी को गिरफ्तार किया गया—शायद आपको मालूम न हो। वहां पर आपकी पार्टी का एम एल ए था, हमारी पार्टी का नहीं था। उस वक्त के आपके होम मिनिस्टर श्री एच एम पटेल ने जो स्टेटमेन्ट दिया था वह मैं बता रहा हूं। तुम्हारी पार्टी (जनता पार्टी) और तुम्हारी सरकार ने बिहार में मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया तुमने बसों में बच्चों को जलाया मुसलमान औरतों और मरदों को जलाया लेकिन आपका एम एल ए दीनानाथ पांडे दनदनाता फिर रहा था। तुमन मौलाना कादरी जोकि रेलिजस लीडर थे उनको पकड़ कर जेल में बेकसूर बंद कर दिया और दूसरे मासूम मुसलमानों को भी पकड़ कर बन्द कर दिया।

बिहार का जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है वह हमेशा से अमन का जिला रहा है। अभी यहां पर कुछ देर पहले एक साहब बैठे हुए थे जोकि वहा पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रह चुके हैं वे इस बात को जानते है कि यह जिला हमेशा पुर-अमन रहा है, सदियों से पुर-अमए रहा है। लेकिन तुम्हारे जनता पार्टी के एम एल ए सूरज नारायण सिंह ने क्या किया? यह एम एल न तुम्हारी पार्टी का था और उसके बाप रामलाल आदि ने जा कर, भवानी नगर, माधो नगर आदि में दंगा कराया जिसमें कितने ही मुसलमानों को मारा गया। 22 लोगों को वहां पर जलाया गया, मैं खुद वहा पर गया हुआ था। मेरे साथी बन्देल पासवान साबिक ए एल ए, बिहार भी वहां पर मौजूद थे और यासीन साहब जोकि कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसीडेन्ट थे वह भी मौजूद थे। ऐसा दर्दनाक मंजर हमने कही नही देखा। वहां पर सूरज नारायण सिंह को जेल में बन्द किया जाना चाहिए था और उसके भाई को जेल में बन्द किया जाना चाहिए था लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस तरह से जनता पार्टी की हकूमत ने बिहार में मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया।

इतना ही नहीं, तुम्हारे साबिक मुख्य मंत्री, कर्पूरी ठाकुर ने जातपांत के नाम पर बिहार में इस कदर दंगे-फसाद कराए जिसमें हजारों लोग मारे गए। तुमने ऐसा बीज बोया है, ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि कितनी ही मेहनत करोगे उस दीवार को तोड़ना मुश्किल होगा। नतीजे के तौर पर चाहे पिपरा हो या दूसरी जगह हो वहां पर रायट्स होते जा रहे है। मैं श्री कमलनाथ जी से एग्री करता हूं कि आगे एलेक्शन्स को मद्दे नजर रखते हुए तुम्हारे लीडर श्री कर्पूरी ठाकुर ने गलत बीज बोकर जो गलत फसल काटने की उम्मीद कर रखी है उसमें वे कामयाब नही हो पायेंगे। तुम्हारी चाल को बिहार के लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं।

इतना ही नहीं, हमारी पार्टी ने बीससूत्री कार्यक्रम शुरू किया था उसके मातहत मैं ने खुद ठाकुरगंज में अपनी अध्यक्षता में तीन सौ लेंडलेस लेबरर्स को अपने हाथ से जमीन के पर्चे बांटे थे। उसके बाद मैं लोकसभा के एलेक्शन में हार गया या इनके मददगार लोगों ने जब मुझे हरवा दिया तो उसके बाद मैं कांस्टीटुएन्सी में गया तब सारे लोग मुझे से कहने लगे कि जमील बाबू, आपने खुद आकर जो जमीन यहां पर बंटवा दी थी वह सारी जमीन वे लोग छीन कर ले गए। इतना ही नहीं सिक्टी मेरा इलाका है, वहां जमीन बटी, दखल दिलाया, सारे गरीब लोगों को, लैंडलैस लोगों को जो करीब 300 थे, जमीन मिली, लेकिन बाद में क्या हुआ, वह जमीन उन से छिन गई। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं—मैंने लिख कर दिया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, शायद उन का नाम श्री के०पी० नारायण था, से कहा कि उन गरीबों की जमीन छिन गई है, मेहरबानी कर के उन की जमीन वापस दिलाइये। मेरे साथ एक अफसर को भेजिये, मैं सब चल कर दिखा देता हूं, उन को वह जमीन वापस दिलाई जाय, लेकिन वह कानों में रूई ठूंस कर बैठ गये और कुछ नतीजा नही निकला।

एक माननीय सदस्य : आप के अपने पास कितनी जमीन है?

श्री जमीलुर्रहमान : 32 एकड़ है। लेकिन आप के पास कितनी है, वह भी बता दीजिये। .....

MR. DEPUTY SPEAKER : When ever any hon. Member raises any issue while sitting, you don't reply to that. It is only to divert your attention; be careful.

श्री जमीलुर्रहमान : अब मैं सिर्फ एक बात कह कर बैठ जाऊंगा। जो पिछली सरकार गई है उस ने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को खराब कर दिया है। जितनी दुकानें हमारे वक्त में थी, सब खत्म हो गई। सत्येन्द्र बाबू ने कुछ आंकड़ दिये हैं—लेकिन मेरे जिले में जो दुर्गति हुई है, मैं कहां तक बयान करूं। दुकानों पर बोर्ड लगे हुए जरूर हैं, लेकिन उन के अन्दर न शक्कर है, न चीनी है। दो-तीन वर्षों के अन्दर उन को पूरी तरह से कमाने का मौका मिला। इतना ही नही जिन पचास हजार लोगों को हमारी पार्टी ने अपने वक्त में जमीनें बांटी, उन सब गरीब और लैण्ड-लेस लोगों को बेदखल कर दिया गया। आप चाहें तो मैं आप को दावत देता हूं, आप मेरे साथ चलें, मैं आप को सब दिखला सकता हूं। हमारी पार्टी ने सब मिला कर 2.5 लाख एकड़ जमीन गरीबों में बांटी थी, लेकिन वह सब उन के हाथ से निकल गई। अब मैं आप से पूछता हूं कि आप की सरकार ने कितनी जमीन बांटी है, आप बतलाइये? हमारे वक्त में लैण्ड-लैस फार्म-लेबरर्स को उस वक्त के डेट-लाज के मुताबिक उन के कर्जों की माफी कर के 1 करोड़ रुपये का फायदा गरीबों को पहुंचाया गया था, मैं पूछता हूं आप ने उन के लिये क्या किया। 15 हजार लोगों को वशोबाश जमीन दी थी, उन को वहां से एविक्ट कर दिया गया, आप ने कितनों को बसाया? बसाना तो दूर रहा, उन को वहां से निकाल दिया गया।

34 करोड़ रुपये का एनुअल प्लान इन की जनता सरकार के वक्त में लैप्स हो गया। इतना ही नहीं 57 करोड़ रुपया अन-यूटिलाज्ड़ रहा, 416 करोड़ रुपये में से कुल मिला कर 139 करोड़ रुपया यूटिलाइज हुआ, बाकी सब लैप्स हो गया—यह आप

की परफार्मेन्स का नमूना है । आप तो जनता का मेन्डेट ले कर आये थे, लेकिन आप ने जनता के लिये कुछ नहीं किया । असल बात यह है कि आप जनता पार्टी के लोग वेस्टेड-इन्टरेस्ट्स के बल पर वहां आये थे, उन्हीं के बल पर हुकूमत करते थे और उन से डरते थे, क्योंकि अगर आप उन के खिलाफ़ कार्यवाही करते तो फिर आप के लिये उन की तिजोरी बन्द हो जाती ।

हमारे दौर में इण्डस्ट्रीज लगाने के लिये जितने लैटर्स आफ़ इन्टेन्ट दिये गये थे, सारे-के-सारे लैटर्स आफ़ इन्टेन्ट को आप ने कैन्सिल कर दिया । अगर मैं यह बात गलत कह रहा हूं तो रिकार्ड आप को बतला सकता है । इसलिये जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं, वह गलत नहीं हैं ।

इतना ही नहीं, एजूकेटेड अनएम्पलाएड के लिये जो स्कीम चली थी, उस को आप की सरकार ने ठप्प कर दिया । आप बतलाइये कितने एजूकेटेड अनएम्पलाएड को आप ने दुकानें दी हैं, राशन शाप्स या बस के पर्मिट दिये हैं, छोटी-मोटी इण्डस्ट्रीज दी हैं ? आप उन के आंकड़े बतला दीजिये ।

हमारे यहां किशनगंज में एक जूट मिल है, जिसका इनआगुरेशन हमारे वक्त में हुआ था । तीन, साढ़े तीन वर्ष हो गये, मगर उसमें एक भी ईंट बिहार की जनता सरकार ने नही जोड़ी । सुना है कि पिछली जनता सरकार उस स्कीम को बन्द करने जा रही थी । मैं कह देता हूं इसके अन्जाम खतरनाक होंगे ।

MR. DEPUTY SPEAKER : It became sick ?

SHRI JAMILUR RAHMAN : We inaugurated it. Then we went out of power and when they came to power, this happened.

अगर ये लोग उसमें एक ईंट भी जोड़ देते, तो मैं इस बात को समझता ।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । आसाम के बारे में जो बहस हुई है, मैंने उसमें हिस्सा नही लिया । मैं कहना चाहता हूं कि इस एजीटेशन के पीछे एक साजिश है । अफ़सरों की इस एजीटेशन के पीछे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स हैं । इस साजिश की वजह से सारे मुल्क को नुकशान हो रहा है । अगर यह कहा जाये कि यह सब एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर धर्म के लिए किया जा रहा है, तो यह कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध है, ग़लत है । इस एजीटेशन के नाम पर नालवाड़ी में कितने ही मुसलमानों, बंगालियों और दूसरे लोगों को बेकुसूर मरवाया गया ।

मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि असम के आई० जी० पुलिस, एन० एफ० रेलवे सिक्युरिटी आफ़िसर और चीफ़ सेक्रेटरी को तुरन्त हटाया जाये, क्योंकि इन लोगों की साजिश नजर आती है । ताकि सिचुएशन कांबू में आये, वहां के सारे लोग अमन-चैन की जिन्दगी गुजार सकें और वहां की पैदावार दूसरे प्रांतों, सूबों और दूसरे देशों में जा सके, जिससे इंडस्ट्रीज और खेती और दूसरी बातों में उसकी तरक्की हो ।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

[شری جمیل الرحمن (کشن گنج) :

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب - بہار کی آبادی قریب ۶ کروڑ ہے اور اس ۶ کروڑ میں قریب ۱۴ فیصدی مسلمان ہیں - بہار ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر ہمارے بزرگوں نے جنم لیا ہے - لارڈ بدھ وہیں کے تھے - حضرت شہباز رحمتہ اللہ علیہ صاحب وہیں کے تھے حضرت مخدوم رحمتہ اللہ علیہ صاحب، وہیں کے تھے - گرو گوند سنگھ صاحب وہیں کے تھے - مہاتما گاندھی نے جو اپنا آندولن شروع کیا وہ بھی وہیں سے کیا اور بھارت نے اپنا پہلا صدر جو دیا وہ بھی بہار سے تھے - مولانا مظہر الحق صاحب وہیں کے تھے - بہت جدوجہد کے بعد جب آزادی آئی اور ہماری پارٹی نے اپنی سرکار بنائی تو ہم لوگوں نے ایک راستہ اختیار کیا - اپنے مینی فیسٹو کے مطابق اور کام آگے بڑھا جس کے ہم لوگ کمیٹڈ تھے - ہم نے اس کام کو آگے بڑھایا - اسی طریقے سے ۱۹۷۱ میں لوگوں نے ایک بھاری اکثریت سے کافی تعداد میں ہم لوگوں کو اپنا ووٹ دیکر لوک سبھا میں بھیجا تھا اور ہم لوگوں نے اپنی پارٹی کے پروگرام کے

پٹیل نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ میں بتا رہا ہوں - (جلتا پارٹی) تمہاری پارٹی اور تمہاری سرکار نے بہار میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا - تم نے بسوں میں بچوں کو جلایا - مسلمان مردوں اور عورتوں کو جلایا لیکن آپ کا ایم - ایل - اے - دینا ناتھ پانڈے دندناتا پھر رہا تھا - تم نے مولانا قادری جو کہ ریلیجس لیڈر تھے ان کو پکڑ کر جیل میں بےقصور بند کر دیا اور دوسرے معصوم مسلمانوں کو بھی پکڑ کر بند کر دیا -

بہار کا جو بورنیہ ڈسٹرکٹ ہے وہ ہمیشہ سے امن کا ضلع رہا ہے - ابھی یہاں پر کچھ دیر پہلے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ وہاں پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ رہ چکے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ضلع ہمیشہ پر امن رہا ہے - صدیوں سے پر امن رہا ہے - لیکن تمہارے (جلتا پارٹی کے) ایم - ایل - اے - سورج نارائن سنگھ نے کیا کیا تھا - یہ ایم - ایل - اے - تمہاری پارٹی کا تھا اور اس کے باپ رام لال وغیرہ نے جا کر بھوانی نگر، مادھو نگر وغیرہ میں دنگا کرایا جس میں کتنے ہی مسلمانوں کو مارا گیا - ۲۲ لوگوں کو وہاں پر جلایا گیا - میں خود جائے وقوع پر گیا ہوا تھا - میرے ساتھی بندیل پاسمان سابق ایم - ایل - اے - بہار بھی وہاں موجود تھے - اور یاسمین صاحب جو کہ

[شری جمیل الرحمن]

مطابق کام کو شروع کیا تھا - چونکہ ہماری پارٹی کو بہاری اکثریت ملی تھی اس لئے یہ بات دوسری ہماری پارٹی کے لوگوں کو بہت کھلی - ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی - جب ہماری پارٹی اپنے سوشل اور اکونومک پروگرام کے اوپر عمل کر رہی تھی اُسی بیچ میں ایک سازش رچا گیا اور اس سے دیش میں ایسی ہوا پھیلائی گئی - ایسے حالات پیدا کئے کہ ایکونو ملک اور سوشل فیلڈ میں ایک جمود آگئی - اس کے نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ جو کام ہم شروع کر رہے تھے یا شروع کر چکے تھے اپنی پارٹی کی لیڈر شریمتی اِندرا گاندھی کی رہنمائی میں اس میں ہر بات پر دخل اندازی کی گئی - ملک میں نفرت کی ایسی فضا تیار کی گئی کہ جو عوامی نمائندہ چن کر آئے تھے ان کی مار پیٹ شروع ہو گئی اور دنگے فساد شروع ہو گئے - سارے بہار میں ایسی فضا پیدا کی گئی کہ دنگے فساد شروع ہو گئے - (ویودھان) جمشید پور میں آپ کا ساتھی (اِشارہ جلتا پارٹی) دینا ناتھ پانڈے گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ مولانا قادری کو گرفتار کیا گیا - شاید آپ کو معلوم نہ ہو - وہاں پر آپ کی پارٹی کا ایم - ایل - اے - تھا - ہماری پارٹی کا نہیں تھا - اس وقت کے آپ کے ہوم منسٹر شری ایچ ایم -

کانگریس پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ تھے وہ بھی موجود تھے - ایسا دردناک منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا - وہاں پر سورج نارائن سنگھ کو جیل میں بند کیا جانا چاہئے تھا اور اس کے بھائی کو جیل میں بند کیا جانا چاہئے تھا لیکن کچھ نہیں ہوا - اس طرح سے جنتا پارٹی کی حکومت نے بہار میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا -

اتنا ہی نہیں تمہارے سابق مکھیہ منتری کرپوری ٹھاکر نے ذات پات کے نام پر بہار میں اس قدر دنگے فساد کرائے جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے - تم نے ایسا بیج بویا ہے - ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ کتنی ہی محنت کروگے اس دیوار کو توڑنا مشکل ہوگا - نتیجے کے طور پر چاہے بہار ہو یا دوسری جگہ ہو وہاں پر رائیٹس ہوتے جا رہے ہیں - میں شری کمل ناتھ جی سے ایگری کرتا ہوں کہ آگے الیکشنس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہارے لیڈر شری کرپوری ٹھاکر نے غلط بیج بو کر جو غلط فصل کاٹنے کی امید کر رکھی ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے - تمہاری چال کو بہار کے لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں -

اتنا ہی نہیں ہماری پارٹی نے بیس سوتری کاریہ کرم شروع کیا تھا اس کے ماتحت میں نے خود ٹھاکرگنج میں اپنی صدارت میں تین سو لینڈ لیس لیبررس کو اپنے ہاتھ سے زمین کے پرچے بانٹے تھے - اس کے بعد میں لوک سبھا کے الیکشن میں ہار گیا یا ان کے مدد گار لوگوں نے جب مجھے ہروا دیا تو اس کے بعد میں کانسٹیچوینسی میں گیا تب سارے لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ جمیل بابو آپ نے خود آکر جو زمین یہاں پر بٹوا دی تھی وہ ساری زمین وہ لوگ چھین کر لے گئے - صرف اتنا ہی نہیں سکتی میرا عدقہ ہے - وہاں زمین بنٹی - دخل دلیا سارے غریب لوگوں کو - لینڈ لیس لوگوں کو جو قریب ۳۰۰ تھے - زمین ملی لیکن بعد میں کیا ہوا وہ زمین ان سے چھن گئی - میں اس بات سے بہت دکھی ہوں - میں نے لکھ کر دیا - ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ شاید ان کا نام شری کے - بی - نارائن تھا - ان سے کہا کہ ان غریبوں کی زمین چھن گئی ہے - مہربانی کر کے ان کی زمین واپس دلائیے - میرے ساتھ ایک افسر کو بھیجئے - میں سب چل کر دکھا دیتا ہوں - ان کو وہ زمین واپس دلائی جائے لیکن وہ کانوں میں روئی ٹھوس کر بیٹھ گئے اور کچھ نتیجہ نہیں نکلا -

ایک مانئیہ سدسیہ : آپ کے اپنے پاس کتنی زمین ہے -

شری جمیل الرحمن : ۳۳ ایکڑ ہے - لیکن آپ کے پاس کتنی ہے - وہ بھی بتا دیجئے . . . .

MR. DEPUTY SPEAKER : Whenever any hon. Member raises any issue while sitting you don't reply to that. It is only to divert your attention ; be careful.

شری جمیل الرحمن : اب میں صرف ایک بات کہہ کر بیٹھ جاؤنگا - جو پچھلی سرکار گئی ہے اس نے سارے ڈسٹریبیوشن چینل کو خراب کر دیا ہے - جتنی دوکانیں ہمارے وقت میں تھیں سب ختم ہوگئیں - ستیندر بابو نے کچھ آنکڑے دئے ہیں - لیکن میرے ضلع میں جو درگتی ہوئی ہے میں کہاں تک بیان کروں - دوکانوں پر بورڈ لگے ہوئے ضرور ہیں - لیکن ان کے اندر نہ غلہ ہے نہ چینی ہے - دو - تین سالوں کے اندر ان کو پوری طرح سے کھانے کمانے کا موقع ملا - اتنا ہی نہیں جن پچاس ہزار لوگوں کو ہماری پارٹی نے اپنے وقت میں زمینیں بانٹیں ان سب غریب اور لینڈ لیس لوگوں کو بےدخل کر دیا گیا - آپ چاہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں - آپ میرے ساتھ چلیں - میں آپ کو سب دکھلا سکتا ہوں - ہماری پارٹی نے سب ملا کر ۲۰۵ لاکھ ایکڑ زمین غریبوں میں بانٹی تھی لیکن وہ سب ان کے ہاتھ سے نکل گئی - اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی سرکار نے کتنی زمین بانٹی ہے - آپ بتلائیے - ہمارے وقت میں لینڈ لیس فارم لیبررس کو اس وقت کے ڈیبٹ لاز کے مطابق انکے قرضوں کی معافی کر کے ایک کروڑ روپئے کا فائدہ غریبوں کو پہنچایا گیا تھا - میں پوچھتا ہوں آپ نے ان کے لئے کیا کیا - پندرہ ہزار لوگوں کو بس و باس زمین دی تھی ان کو وہاں سے ایوکٹ کر دیا گیا - آپ نے کتنوں کو بسایا - بسانا تو دور رہا ان کو وہاں سے نکال دیا گیا -

۳۴ کروڑ روپئے کا سالانا پلان ان کی جنتا سرکار کے وقت میں لیپس ہو گیا - ۴۱۶ کروڑ روپئے میں سے کل ملا کر ۱۳۹ کروڑ روپیہ یوٹیلائز ہوا - اتنا ہی نہیں ۵۷ کروڑ روپئے ان یوٹیلائزڈ رہے باقی سب لیپس ہو گیا - یہ آپ کی پرفرومینس کا نمونہ ہے - آپ تو جنتا کا مینڈیٹ لے کر آئے تھے - لیکن آپ نے جنتا کے لئے کچھ نہیں کیا - اصل بات یہ ہے کہ آپ جنتا پارٹی کے لوگ ویسٹڈ انٹریسٹ کے بل پر وہاں آئے تھے انہیں کے بل پر حکومت کرتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے - کیونکہ اگر آپ ان کے خلاف کاروائی کرتے تو پھر آپ کے لئے ان کی تجوری بند ہو جاتی -

ہمارے دور میں انڈسٹریز لگانے کے لئے جتنے لیٹرس آف انٹنٹ دئے گئے تھے - سارے کے سارے لیٹرس آف انٹنٹ کو آپ نے کینسل کر دیا - اگر میں یہ بات

غلط کہہ رہا ہوں تو رکارڈ آپ کو بتا سکتا ہے - اس لئے جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے -

اتنا ہی نہیں ایجوکیٹڈ ان ایمپلائڈ کے لئے جو اسکیم چلی تھی اس کو آپ کی سرکار نے ٹھپ کر دیا - آپ بتلائیے کتنے ایجوکیٹڈ ان ایمپلائڈ کو آپ نے دوکانیں دی ہیں - راشن شاپ کے پرمٹ دئے ہیں - چھوٹی موٹی انڈسٹریز دی ہیں - آپ ان کے آنکڑے بتلا دیجئے -

ہمارے یہاں کشن گنج میں ایک جوٹ مل ہے جس کا انوگریشن ہمارے وقت میں ہوا تھا - تین ساڑھے تین سال ہو گئے مگر اس میں ایک بھی ایلمٹ بہار کی جنتا سرکار نے نہیں جوڑی - سنا ہے کہ پچھلی جنتا سرکار اس اسکیم کو بند کرنے جا رہی تھی - میں کہہ دیتا ہوں اس کے انجام خطرناک ہونگے -

MR. DEPUTY SPEAKER : It became sick.

SHRI JAMILUR RAHMAN : We inaugurated it. Then we went out of power and when they came to power, this happened.

اگر یہ لوگ اس میں ایک ایلمٹ بھی جوڑ دیتے تو میں اس بات کو سمجھتا -

آخر میں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں - آسام کے بارے میں جو بحث ہوئی ہے میں نے اس میں حصہ نہیں لیا - میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایجیٹیشن کے پیچھے ایک سازش ہے - افسروں کی اس ایجیٹیشن کے پیچھے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں - اس سازش کی وجہ سے سارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے - اگر یہ کہا جائے کہ یہ سب ایک پرٹیکولر ایریا یا ایک پرٹیکولر دھرم کے لئے کیا جا رہا ہے تو یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے غلط ہے - اس ایجیٹیشن کے نام پر نالباری میں کتنے ہی مسلمانوں، بنگالیوں اور دوسرے لوگوں کو بے قصور مروایا گیا -

میں سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ آسام کے آئی - جی - پولیس - این - ایف - ریلوے سیکیورٹی افسر اور چیف سیکریٹری کو فوراً ہٹایا جائے کیونکہ ان لوگوں کی سازش نظر آتی ہے - تاکہ سچوایشن قابو میں آئے - وہاں کے سارے لوگ امن چین کی زندگی گذار سکیں اور وہاں کی پیداوار دوسرے پرانتوں، صوبوں اور دوسرے دیشوں میں جا سکے - جس سے انڈسٹریز اور کھیتی اور دوسری باتوں میں اس کی ترقی ہو -

ان الفاظ کے ساتھ میں ان مانگوں کی تائید کرتا ہوں -]

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : सभापति महोदय, आज जब आर्थिक पिछड़ेपन की बात आती है, राजनैतिक पिछड़ेपन की बात आती है और सामाजिक पिछड़ेपन की बात आती है, तो बिहार का नाम लिया जाता है।

[श्री तारिक अनवर]

अभी विरोधी दल के एक सदस्य ने 1974 के छात्र आंदोलन का जिक्र किया। मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1974 में बिहार के छात्रों, बेरोजगार नौजवानों, किसानों, मजदूरों और समाज के हर एक वर्ग को एक स्वप्न दिखाया गया, एक ख्वाब दिखाया गया। उन्हें कहा गया कि अगर तुम हमारी पार्टी को वोट दोगे और इन्दिरा गांधी के शासन को खत्म कर दोगे, तो हम तुम्हें रोजगार देंगे, बिजली देंगे, आवश्यकता की दूसरी चीजें देंगे और तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान कर देंगे। लेकिन 1974 के उस मूवमेंट में जिन नौजवानों और छात्रों ने कुर्बानियां दीं, जो जेल गये, आज भी वे बेरोजगार हैं और आज भी उसी तरह नरक की जिन्दगी बिता रहे हैं। हां, यह सही है कि उस आन्दोलन के बाद चुनाव हुए और उस चुनाव में कुछ नौजवान साथी जीत कर आए, कुछ विधान सभा में गये और कुछ लोक सभा में गये। उन की आशाएं जरूर पूरी हो गयीं, उन की तमन्ना थी हवाई जहाजों में सफर करने की और बड़े बड़े मकानों और फ्लेटों में रहने की और वह पूरी हो गई लेकिन नौजवान जो बेरोजगार थे, जो किसान बिजली के लिए तरसते थे, जो डीजल के लिए तरसते थे, उन मजदूरों के, जिन को 20 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा हमारी सरकार ने जमीन दी थी, मकान दिये थे, सारे मकानात छीन लिये गये, उन की जमीनें छीन ली गई और उन को अगर कुछ मिला, तो सिर्फ निराशा मिली, नाउम्मीदी मिली और इतना ही नहीं अभी जो यहां पर चर्चा हो रही है, पिछले दिनों जो हमारी सरकार थी, हम ने आजादी के बाद 30 सालों में जो हिन्दू-मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए, इस एकता को मजबूत करने के लिए, भाई को भाई से मिलाने के लिए जो कोशिश की थी, हम ने जो हिन्दू-मुसलमानों के बीच नफ़रत कम करने की कोशिश की थी, इन ढाई सालों में जनता पार्टी और लोक दल की सरकारों ने फिर से सारे देश के अन्दर और खास तौर से बिहार में हिन्दू और मुसलमानों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है और जो पुल हम ने बनाये थे, उन को तोड़ दिया और इस से भी इन को चैन नहीं मिली। इन्होंने न सिर्फ हिन्दू-मुसलमानों को बल्कि एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया और जो नौजवान, जो छात्र होस्टलों में एक बेड पर सोते थे, एक साथ रहते थे और उस में उन की जिन्दगी बीत गई थी, वे भी एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गये हैं और एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो बिहार के प्रशासन की हालत रही है, जो ला एण्ड आर्डर की पोजीशन वहां रही है, वह आप के सामने है। आप पिछले ढाई साल में जमशेदपुर के वाक्या को लीजिए। जमशेदपुर से ले कर पिपरा के वाक्यात को अगर लिया जाए, तो आप देखेंगे कि इन ढाई सालों में क्या हुआ है। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि ढाई साल में पहली बार हरिजनों की सामूहिक रूप से बेलछी में हत्या हुई है और इसका एक ही कारण था कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जो बड़े बड़े किसान थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने इस बात को समझा कि अब उन की सरकार बन चुकी है, इसलिए अब उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है और पिछली कांग्रेस सरकार के बदलने के बाद, कांग्रेस शासन के समाप्त होने के बाद फौरन अल्पसंख्यकों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों पर जुल्म बढ़ते गये और उन लोगों के खिलाफ़, जिन्होंने ये जुल्म किये थे, कोई कार्यवाही नही की गई। जमशेदपुर की घटना के बारे में जमीलुर्रहमान साहब ने यहां पर बताया ही है। मैं इस बात को मानता हूं कि पिछले दिनों में भी फिरकावाराना फ़साद होते रहे हैं, हिन्दू-मुसलमानों में झगड़े हुए हैं लेकिन उन को दो दिन के अन्दर, चार दिन के अन्दर ही कन्ट्रोल कर लिया गया लेकिन अब आप यह देखें कि जमशेदपुर में जो वाक्यात हुए या अलीगढ़ और दूसरी जगहों पर जो ऐसे वाक्यात हुए, तो छः छः महीने तक वे दंगे चलते रहे, वाकयात होत रहे लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और उन को इस बात का अहसास नहीं हुआ कि किन लोगों ने जुल्म किये हैं बल्कि उन्होंने उन की ही तरफ़दारी की। उन की पार्टी के लोगों ने भी इस बात को कहा कि जमशेदपुर में दंगे करवाए गये और वे आज भी ऐसा काम कर रहे हैं। जब इस तरह की बातें हुई तो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों ने इस बात को महसूस किया मुसलमानों ने और हरिजनों ने यह महसूस किया कि हम असुरक्षित हैं और यही कारण है कि जब पिछला चुनाव हुआ, तो समाज के उन सारे कमजोर वर्गों ने इन्दिरा कांग्रेस को वोट दिया क्योंकि उन को यह अहसास हुआ कि इन्दिरा गांधी जी के बीस सूत्री कार्यक्रम से ही उनका कल्याण हो सकता है, उनका भला हो सकता है।

जहां तक बजट का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार के अन्दर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। वैसे तो यह सारे देश की समस्या है लेकिन बिहार जो हिन्दुस्तान का एक पिछड़ा हुआ इलाका है, सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी, सारी चीजें रहने के बावजूद आज भी वहां प्रगति नहीं हो रही है और वह आज भी एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और वहां पर बेरोजगारी की समस्या बड़ी जटिल हो चुकी है। अगर इस पर अविलम्ब ध्यान नही दिया गया, तुरन्त ध्यान नहीं दिया गया, तो हो सकता है इकि आगे चल कर एक आन्दोलन चले और कही ह डतना आगे न बढ़ जाए कि जिस से ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम वहां पर बन जाए। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहूंगा कि बेरजगारी की जो समस्या है उस को दूर करने की कोशिश की जाए चाहे स्माल स्केल इंडस्ट्री खोल कर और चाहे दूसरे छोटे छोटे उद्योग धंधे खोल कर। उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए ताकि जो आर्थिक सहायता का बोझ है उस से वे छुटकारा पा सकें और अपना विकास कर सकें।

आज बिहार के अन्दर विश्वविद्यालय की क्या हालत है? शिक्षा संस्थानों की क्या हालत है? वह इतनी दयनीय हो चुकी है कि उस के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन में और सरकार की दूसरी संस्थाओं

में जात-पांत चल रहा है उसी तरह विश्वविद्यालयों में और कालेजों में भी उसकी जड़ मजबूत होती जा रही है। वहां दो-दो साल और तीन-तीन साल से एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं। आज वहां के छात्रों के जीवन, उनकी बेरोजगारी का सवाल है। इन सब चीजों पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

सूखे की हालत का भी अभी जिक्र हुआ। बिहार के अन्दर हर जगह सूखा ही सूखा नजर आ रहा है। आज बिहार के लोग सूखे से पीड़ित हैं। उस के बावजूद भी उनको जो सुविधाएं और साधन मिलने चाहिएं वे उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में जो हमारे भाई और किसान भाई रहते हैं उनकी समस्याओं को हल किया जाए, उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाए ताकि उनके अन्दर इस बात का अहसास हो कि वे किसी सरकार के अधीन रहते हैं, उनके ऊपर कोई हुकूमत है। उनके ऊपर प्रांत में कोई हुकूमत चल रही है इस बात का उन्हें अहसास होना चाहिए।

पिछले दिनों जो जमीन का बंटवारा किया गया था, जिन मजदूरों के पास जमीन नही थी और उनको रहने के लिए, मकानों के लिए जमीनें दी गयी थीं वह पिछले ढाई सालों में उनसे छीन ली गयी है, उनस मकान छीन लिये गये हैं। फिर से इस बात की कोशिश होनी चाहिए जो ऐसे भूमिहीन लोग है उनको फिर जमीनें दी जाएं और फिर से लैण्ड रिफार्म्स का काम शुरू किया जाए ताकि जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको हम कुछ सुविधा पहुंचा सकें। इन्ही बातों के साथ जो दूसरी समस्याएं हैं, दूसरी बातें है जिनका कि यहा जिक्र हो चुका है, मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, उन सभी पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और गरीब लोगों को राहत पहुंचायी जानी चाहिए।

एक बार मैं फिर यह कहूंगा कि गरीब लोगों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। आखिर में मैं यह कह कर अपनी बात खत्म करता हूं कि अगर बिहार की समस्याओं पर, बिहार के किसानों और मजदूरों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आज जो लोग बेरोजगार हैं, उनके जीवन को गुजारने की बड़ी समस्या है, उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इन बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार प्रांत के बजट पर चर्चा चल रही है। वहां कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर हमारे माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। यों तो पूरे बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत भयानक है मगर बेगुसराय की स्थिति और भी ज्यादा भयानक है। बिहार में यह एक ऐसा जिला है जहां एक तस्कर गिरोह है जिसका सरदार कामदेव सिंह एक कांग्रेसी है और जिसके बारे में आपके माध्यम से इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं। बिहार में सरकारें आयीं और गयी लेकिन वह तस्कर गिरोह पिछले बीस वर्षों से न सिर्फ केवल बेगुसराय जिले में बल्कि दूसरे स्थानों में भी आतंक बरपा कर रहा है। उसके आपरेशन का एरिया नेपाल, बिहार के कई जिले, कलकत्ता, कानपुर और पता नही कहां कहां है। उसके गिरोह में कई सौ लोग संगठित रूप से काम करते हैं। वह ऐसा गिरोह है जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। उसके पास रायफलें, सैल्फ लोडिंग राइफल्ज, स्टेन गन, एल एम जी आदि अत्याधुनिक हथियार हैं। 1962 में वह एक गाड़ीवान था और आज 1980 में वह करोड़ों का मालिक है। आश्चर्य की बात है कि उसके ऊपर सैंकड़ों मुकदमें विचाराधीन पड़े हैं लेकिन आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस वजह से लगातार वहां हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। सौ से ज्यादा लोग उसके गिरोह द्वारा मारे जा चुके हैं।

1967 के बाद से उसने राजनीतिक हत्यायें करनी शुरू की, यह सब से ज्यादा चिन्ता की बात है। दुख की बात तो यह है कि उसको राजनीतिक प्रोटैक्शन मिलता है और उसकी वजह से प्रशासन उसके ऊपर उंगली तक नहीं उठा सकता है। उस की समानान्तर सरकार है। लाखों रुपया खर्च करके बेगुसराय जिले में ही नही बल्कि दूसरे जिलों में भी उसने छोटे बड़े अफसर खरीदे हुए हैं। इस वास्ते कोई उसके खिलाफ उंगली नही उठा सकता है। अगर कोई इस गैंग के खिलाफ आवाज बुलन्द करने का दुस्साहस करता है तो उसकी जिन्दगी सुरक्षित नहीं रह सकती है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उस गैंग का हत्या करने का भी एक अजीब तरीका है। पहले तो जिसकी हत्या करनी होती है उस व्यक्ति का अपहरण किया जाता है, उसको किडनैप किया जाता है और फिर सिर से पैर तक उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उस व्यक्ति की लाश तक का पता नही चलता है। जब पुलिस को कोई खबर दी भी जाती है तो वह मूक दर्शक बन कर देखती रहती है और उस गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नही करती है। आपको सुन कर हैरानी होगी कि 1977 में भटिहानी क्षेत्र के एक कम्युनिस्ट एम० एल० ए० जो जीत कर आए थ उन्होंने कामदेव गैंग के आतंक की चर्चा बिहार असैम्बली में की थी और अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि चूंकि वह कामदेव सिंह के खिलाफ आवाज बुलन्द कर रहे हैं, बिहार असैम्बली में इस वास्ते फिर उनकी आवाज दूसरी बार वहां नही सुनी जा सकेगी और हुआ भी यही। एक ही महीने में उनकी हत्या कर दी गई। सरेआम, नेशनल हाई वे पर स्टेन गन से उनकी हत्या कर डाली गई। आज भी सीता राम मिश्र का हत्यारा नेशनल हाइवे पर घूमता है और जब हम लोग पुलिस को खबर देते हैं तो उसकी निगाह भी उसके खिलाफ नहीं उठती है। यह गुन्डागर्दी का आलम है। कामदेव सिंह के

[श्री सूर्य नारायण सिंह]

गैंग ने सिहमा गांव जो बेगूसराय में है, एक साल में पांच हत्यायें की हैं। आज से कुछ महीने पहले हथियारबन्द पुलिस और एक दारोगा के संरक्षण में जब कुछ लोग अपनी फसल काटने के लिए जा रहे थे तो कामदेव सिंह के गिरोह ने गोली चलाई पुलिस के सामने और दो बूढ़े मार डाले गये। एक तो सत्तर साल का बूढ़ा था उसकी लाश गिरी लेकिन पुलिस मूक दर्शक बन कर खड़ी रही। क्या कोई प्रशासन बेगूसराय में और बिहार में है या हो सकता है?

23 फरवरी को 23 साल का एक लड़का फुलेना सिंह जो अपनी फसल को देखने के लिए जा रहा था मकई के खेत में छुपे हुए इस गिरोह के गुन्डों ने उस पर स्टैन गन से 14 गोलियां चलाई जो उसके सीने आदि पर लगीं और उसकी मृत्यु हो गयी। यह प्रशासन है। पहले कहा जाता था कि चूंकि जनता पार्टी का राज्य है, इस लिए ऐसा होता है लेकिन अब क्या बात है और क्यों इस तरह की घटनायें होती हैं?

श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव के वक्त अपने भाषणों में लम्बी लम्बी बातें कही थी और कहा था कि कानून और व्यवस्था की हिफाजत करने के लिए उनको सत्ता में लाया जाये। लेकिन आज भी वह गिरोह कांग्रेस के शासन में पलता है, उसको इसके द्वारा संरक्षण दिया जाता है। इसके खिलाफ अगर कोई आवाज बुलन्द करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। राह चलते राहजन को गोली मार दी जाती है। कोई राजनीतिक कार्यकर्ता उसके खिलाफ आवाज बुलन्द करता है तो उसके सीने से गोली पार कर दी जाती है। करोड़ों रुपये की सम्पत्ती उसके पास है। तस्कर विरोधी कानून बना हुआ है लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही होती है। मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूं कि एमरजैन्सी जब लगी थी तब हम लोगों को तो, हजारों लोगों को तो गिरफ्तार करके जेलों में ठूंस दिया गया था लेकिन कामदेव सिंह के गिरोह के लोगों को तब भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। आप कानून और व्यवस्था स्थापित करने की बात करते है लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता है। राजनीति करने वाला खुलकर बात भी नहीं कर सकता है, इस गुन्डागर्दी के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता है। जिस राज्य में राजनीति करने वाले खुलकर बात नहीं कर सकते, गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज नहीं निकाल सकते, यही स्थिति बेगुसराय की है।

आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने पटना के चीफ सैक्रेटरी, आई० जी० से भी बात की है, कल हमने गृह-मंत्री से भी बात की है, स्मारक-पत्र दिया है और अब यह बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई है। हम आप के माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अगर इस गैंग को निर्मुल करने के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये तो हमने तय किया है कि 20 तारीख से हम जिला कलक्टर के आफिस के सामने रिले-फास्ट करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम कहना चाहते हैं कि बेगुसराय की जनता कायर नहीं है, वह गुंडागर्दी का मुकाबला करना जानती है और अगर कोई भी घटना घटी बेगुसराय की जमीन पर तो इसकी जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट की होगी। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri Ranjit Singh. One request. Every one of the Hon. Members will take only seven minutes; you will take only seven minutes. I think you may be able to conclude within five minutes.

श्री रणजीत सिंह (चतरा): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के इस बजट का जब मैं समर्थन कर रहा हूं तो यह भी कहना चाहता हूं कि इस बजट में बहुत सारी कमियां हैं। समूचे बिहार में पानी के लिये केवल 18 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई है। हमारा बिहार सभी राज्यों से बहुत पीछे पड़ा हुआ है। यहां बहुत से गांव है। यहां 66 लाख गांव में बसने वाली जनता के लिये कोई पीने के पानी का इंतजाम नही किया गया है। शुरू से जब से हमारी कांग्रेस की सरकार थी, आजादी के बाद यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी दी जायेगी, लेकिन बिहार में तीनों आजादियों में से आज तक एक भी आजादी नही है वहां आर्थिक आजादी नही है, वहां के पढ़े-लिखे लोगों को कोई रोजगार नहीं है। आपातकाल के दिनों में हमारी सरकार ने बहुत सी बसें दी थी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने उन सब को बन्द कर दिया जिससे हमारे यहां के बहुत से लोग अब बेरोजगार हैं।

इसी तरह से हमारे राज्य में कहीं भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वह सारा क्षेत्र छोटा नागपुर में पड़ता है, वहां चतरा क्षेत्र में आदिवासियों और हरिजनों की संख्या बहुत है। वहां के लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं है, पीने का पानी नहीं है, दो-दो और चार-चार कोस पर स्कूल हैं जहां आकर लोग शिक्षा नहीं पा सकते हैं। इस तरह से हमारे बिहार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अफसर लोगों ने कोई भी ऐसा कारगर कदम नहीं उठाया जिससे हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा कोई इंडस्ट्री लगाई जाये जिससे बेरोजगारी की समस्या हल हो।

बिहार सरकार ने अभी तक किसी स्टेडियम का भी इंतजाम नहीं किया है। डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम होना चाहिए जहां कि लोग फिजिकल एजूकेशन प्राप्त कर सकें। वहां इसका कोई भी स्कूल, कालेज या यूनिवर्सिटी नहीं बन पाया है।

बजट में यह भी प्रावधान है कि "बैकवर्ड पीपल्स के वैलफेयर पर 3 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा, लेकिन उसकी कोई भी डैफिनिशन नहीं दी गई है कि बैकवर्ड क्लास की डैफिनिशन क्या है। जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने उस समय इसकी डैफिनिशन इकनामिक कंडीशन पर नहीं, बल्कि जातीय आधार पर बनाई थी जो कि सरासर गलत है और समाज पर कलंक है। वैसे श्री कर्पूरी ठाकुर की सरकार में जातीय आधार पर पिछड़ी जातियों की लड़ाई बहुत चली और उसी तरह से वहां कर्पूरी ठाकुर और लोकदल के नेताओं ने लोगों को बहुत कन्फ्यूज किया जिसके कारण ही पिपरा वगैरह के कांड हुए हैं।

15.00 hrs.

जनता पार्टी की सरकार ने बिहार की इकानोमिक कन्डीशन को बिगाड़ दिया था, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक इन तीनों आजादियों को कम कर दिया था और लोगों को तबाह कर दिया था। वहां के लोगो की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स या स्पेशल पुलिस की स्थापना की जाये और बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाये।

इस बजट में कूलड प्रोटेक्शन के लिए रुपया रखा गया है। आज बिहार के 40,000 गांवों में अकाल पड़ा हुआ है। फिर भी वहां न तो लाल कार्ड दिये जाते हैं और न डीजल या कैरोसीन तेल दिया जाता है। आज बिहार की जनता भूखों मर रही है और बेरोजगारी व्यापक पैमाने पर फैली हुई है। मैं आप के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन 40,000 गांवों में शीघ्रातिशीघ्र राहत-कार्य का इन्तजाम किया जाये।

बिहार के शहरों में पानी की व्यवस्था करने की बहुत आवश्यकता है। इस काम के लिए सारे बिहार के लिए 10, 12 करोड़ रुपये रखे गये है। जब कि केवल एक शहर में पानी की व्यवस्था के लिए दो चार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस थोड़ी सी धनराशि से सारे बिहार में पानी की व्यवस्था कैसे हो सकेगी ? इसलिए बिहार के विकास के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए बजट में अधिक रुपये का प्राविजन किया जाये।

माननीय सदस्य, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, ने कहा है कि बिहार एसेम्बली को डिजाल्व कर के बहुत अन्याय किया गया है। मैं इस बारे में अपना मतभद प्रकट करना चाहता हूं। केवल बिहार सरकार ही नहीं, कई अन्य राज्य सरकारों को भी बर्खास्त किया गया है, क्योंकि उन पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है। जब जनता पार्टी की सरकार ने नौ स्टेट्स की एसेम्बलीज को डिजाल्व किया था, तो कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी को अब वहां की जनता का विश्वास नहीं प्राप्त है। यह भी कहा गया था कि उस समय कांग्रेस के सारे उम्मीदवार हार गये थे, जिससे उन पर लैक आफ़ कान्फ़िडेंस प्रकट होता है, इस लिए उन राज्यों की एसेम्बलीज को डिजाल्व कर दिया गया।

भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में कहा गया है कि जब प्रेजिडेंट को मालूम हो कि कोई राज्य सरकार भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चल सकती है, तो उन्हें उस सरकार को बर्खास्त करने और एसेम्बली को डिजाल्व करने का पूरा अधिकार है। बिहार में जात-पात का नंगा नाच हो रहा था, लोग भूखों मर रहे थे और गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। क्या उस समय वहां की सरकार संविधान के अनुसार चल रही थी ? इस लिए आज यह डिसोल्यूशन ठीक हुआ है। अगर उचित समय पर यह डिसोल्यूशन न होता, तो लोग भूखों मर जाते और ला एंड आर्डर न होने की वजह से न जाने कितने लोगों की जानें चली जातीं।

लोक सभा के इन चुनावों में जनता पार्टी को केवल 8 सीटें और लोक दल को केवल 5 सीटें मिल सकी। इस प्रकार दोनों पार्टियों के केवल 13 सदस्य चुने गये, जबकि बिहार में कुल सदस्य संख्या 54 है। इस स्थिति में, प्रेजिडेंट ने एसेम्बली का जो डिसोल्यूशन किया वह बिल्कुल ठीक है।

अन्त में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता की स्थिति को सुधारने के लिए 20-पायंट प्रोग्राम को पूरी तरह से लागू किया जाये, जिसका वचन हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में किया गया है। इस बारे में अफसरों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहना चाहिए। इस समय अनाज, डीजल और मिट्टी के तेल में चोरी हो रही है। इस बारे में पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव्ज द्वारा विजिलेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए।

15.05 hrs.

[SHRI SHIVRAJ V. PATIL *in the Chair*]

श्री एन० ई० होरो (खूंटी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार के 3-6 प्रखन्डों में अकाल की स्थिति है। हमने आशा की थी कि राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद जब केन्द्रीय सरकार बिहार की बाग-डोर सम्भाल लेगी, तो कुछ सुधार होगा। लेकिन हमने देखा कि सुधार के बजाय और खराबी हो रही है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 316 प्रखन्डों में जो अकाल की स्थिति आई हुई है वहां सरकार ने राहत कार्य चलाने की योजना शुरु की है। फूड फार वर्क के माध्यम से राहत कार्य चलाने की योजना है। मगर स्थिति यह है कि दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर प्रमण्डल के अन्दर आज के दिन तक 12 हजार मैट्रिक टन गेहूं उन लोगों को नहीं मिला है जिन्होंने एक डेढ़ महीने से वहां काम किया है। अनाज वहां पहुंचा ही नहीं। आदेश यह है कि हर प्रखन्ड में कम से कम दो राहत के काम चलने चाहिए और

[श्री एन० ई० होरो]

प्रतिदिन नही तो हफ्ते में उनको गेहूं मिलना चाहिए। लेकिन आप अन्दाज कर सकते है कि 12 हजार मैट्रिक टन गेहूं दक्षिणी छोटा नागपुर में बकाया है। केन्द्र की सरकार इसके लिए क्या कर रही है? लाल कार्ड जो लोगो को दिया गया है जो डिसएवल्ड लोग हैं, गरीब लोग है उनको उस लाल कार्ड से आज भी एक दाना भी वितरण नही हुआ है और कहा यह जाता है कि फूड फार वर्क के तहत यह सारा काम हो रहा है। जितना गेहूं जाता है वह देहातो तक पहुंच नही पाता है। उसका पचास प्रतिशत तो कही न कही खो जाता है, वह देहातों को पहुंचता नही है। यह हालत है। वहां फेमिन डिक्लेयर किया गया है तो फेमिन कोड के तहत वहां काम होना चाहिए लेकिन वह हो नही रहा है। हमने वहा की राज्य सरकार के अधिकारियों से और स्थानीय अधिकारियो मे यह बात कही कि आप अभी से अगर उन क्षेत्रों में जहां कि फेमिन चल रही है दवाई का प्रबन्ध नही करेंगे और पानी का इंतजाम नही करेंगे तो वहां की दशा और खराब होगी लेकिन राज्य सरकार उस फेमिन कंडीशन को टैकिल करने के लिए तैयार नही है, न पहले इसके लिए वह तैयार थी और न अभी है। यह वहां की हालत है। जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर है श्री भीष्म नारायण सिह, वह पलामू जिले से आते है, पता नही, इन को मालूम है या नही, इन के जिले के मनिका प्रखन्ड में कितने ही लोगो की भूख से मृत्यु हो गयी है। लोग वहा मर रहे हैं और सरकार उस को छिपाना चाहती है। भीष्म नारायण बाबू इसको जानते है, मगर यह बात छिपायी जा रही है।

सवाल यह है कि राष्ट्रपति शासन मे काम सुधरना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते थे। लेकिन यहा तो कांग्रेस वाले जनता पार्टी को गाली देते हैं और जनता पार्टी वाले कांग्रेस को गाली देते है। मै किसी को गाली नहीं देना चाहता हूं। 30 साल तक कांग्रेस ने वहा हुकूमत की, आप ने क्या किया जो बिहार पिछड़ गया? बिहार क्यों पीछे पड गया? जो आज रोना रोते है और केन्द्र मे आते हैं भीख मागने के लिए कि इडस्ट्री नही है, यह नही है, वह नहीं है, यह किस का काम है? 30 साल मे आप ने क्या किया? दो साल जनता पार्टी ने शासन किया। वे कहते है कि उन्हे लरनर को लाइसेंस था वे ठीक से काम नहीं कर पाय। दोनो के राज्य मे मुसलमानो की हत्या होती रही, हरिजनो की हत्या होती रही। इसलिए यह मत कहिए कि वह गलत हैं, हम सही हैं। हम सब उसके लिए दोषी हैं कि बिहार को आगे नही बढ़ाया।

मैं श्री भागवत झा आजाद की बात से सहमत हूं और बहुत दिनों से कहता रहा हू कि बिहार का प्रशासन इतना गंदा है, इतना करप्ट है, पालिटिशियंस ने उस को इतना प्रभावित किया है कि चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे केन्द्र की सरकार वहां काम करे, उस प्रशासन के माध्यम से काम चलने वाला नही है। प्रशासन को साफ करना होगा, तभी काम हो सकता है, नही तो रुपया आप यहां से भेजेंगे वह रुपया बिल्कुल बेकार जायेगा और यों ही खत्म हो जायेगा। हमारे कुछ मित्रो ने कहा कि इतने करोड़ इतने हजार रुपया खर्च नही हुआ है। खर्च तो बराबर ही नही होता रहा है। 30-32 साल में बराबर यही स्थिति रही है। हर साल का आप देखेंगे तो पाएंगे, कितने ही विभागों को विकास के लिए रुपया मिलता रहा है, उस का उन लोगों ने पूरा पूरा उपयोग नही किया। चूंकि प्रशासन इनएफीशिएन्ट है इसलिए यह हो रहा है। इसलिए जब तक इसको बदला नही जायेगा तब तक प्रगति नही हो सकती है।

एक बात मैं और कहना चाहता हू हमारे जिले राची मे कोइल-कारो हाइडल प्रोजेक्ट बनने वाला है। नेशनल हाइडल प्रोजेक्ट ने इसको ले लिया है और काम शुरू होने वाला है। उसके अन्तर्गत जो लोग विस्थापित होने वाले है, चूंकि कई गाव पानी मे चले जायेंगे, उनका जब तक इकोनोमिक रिहैबिलिटेशन नही हो जाता तब तक उसका काम शुरू नही होना चाहिए। हमारे लोगो ने काम बन्द करवा रखा है। मै सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहता हू कि आप प्रोजेक्ट बनाये लेकिन इससे पहले विस्थापित होने वाले लोगो का एकोनामिक रिहैबिलिएटेशन हो जाना चाहिए। आपने कम्पेन्सेशन का रुपया दे दिया और उसके बाद छुट्टी-ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उन लोगो का एकोनामिक रिहैबिलिटेशन करके ही काम शुरू होना चाहिए।

लैण्ड रिफार्मस के बारे मे बहुत कुछ कहा जाता रहा है लेकिन मै कहना चाहता हू कि बिहार मे जो ट्राइबल एरियाज है वहा पर लैण्ड रिफार्म्स जैसी कोई चीज नही है। लैण्ड रिफार्म्स के नाम पर सर्वे सेटिलमेन्ट आपरेशन चल रहा है लेकिन इसमें जो सेटिलड है उनको अन-सेटिल्ड किया जा रहा है। 50-60 साल पहले से जो जमीन आदिवासियो के पास थी वह उनके हाथ से छीनी गई है और यह काम रेवेन्यु डिपार्टमेंट के माध्यम से हो रहा है। इसके लिए 50 प्रतिशत जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेन्ट और ला कोर्टस पर जाती है। कचहरियों में ज्यादा पैसा लगाकर आप न्याय खरीद सकते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार मे हरिजन आदिवासियो की बहुत सारी जमीन उनके हाथ से चली जा रही है क्योंकि वे न्याय खरीद नही सकते। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। एलेक्शन के बाद रूलिंग पार्टी की सरकार अगर वहा पर आती है तो उसको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वहा के आदिवासियों में जमीन की समस्या का समाधान अगर नही होगा तो स्थिति

और खराब हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, बिहार के लिए जो बजट पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री कमलनाथ झा ने बिहार के स्वर्णिम इतिहास का चित्रण किया, सम्राट अशोक से लेकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद तक। लेकिन बिहार के मस्तक पर जो एक कलंक का टीका लगा हुआ है उसका चित्रण उन्होंने छोड़ दिया। वह कलंक का टीका न केवल भारत के लिए, न केवल बिहार के लिए, वह सम्पूर्ण विश्व के लिए है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ, जिसने जन्म के तुरन्त बाद सत्ता सभाली, जिसका न कोई सिद्धान्त, न कोई लक्ष्य, न कोई उद्देश्य है और उस जनता पार्टी का जन्म बिहार में ही हुआ और बिहार में जनता पार्टी के शासन के बाद भारतवर्ष तो पीछे गया ही, भारत वर्ष का सम्मान तो घटा ही, उससे बिहार भी अछूता नहीं रहा, बिहार भी उसमें काफी पीछे हो गया। जहां बिहार में आन्तरिक रिसोर्सिस को बढ़ाने की बात योजना आयोग ने समझौते के अनुसार की थी, जहां बिहार में 131 करोड़ रु० जो आन्तरिक सोर्स से हम इकट्ठा करते थे और योजना आयोग के समझौते के अनुसार कि हम दो सौ करोड़ रु० जुटायेंगे, परन्तु जनता पार्टी के शासन में वह रुपया बढ़ने के बजाए घटा और मात्र 11 करोड़ रु० इकट्ठा किया। जनता पार्टी के शासन में जनता पार्टी ने जनता के हित को छोड कर अपने लक्ष्यों के लाभ के लिए वहां कई कदम उठाए जिसका कुप्रभाव बिहार के विकास पर पड़ा।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार में नशाबन्दी कानून लागू किया गया, उसके पीछे इनका राजनीतिक उद्देश्य था, इनकी योजना थी और कहा गया कि इसको चार चरणों में लागू किया जाएगा, लेकिन एक चरण तो इनका पूरा हुआ, बाकी तीन चरण इनके पूरे नहीं हो सके और उनसे बिहार राज्य को 30 करोड़ रु० के राजस्व का घाटा हुआ। बिहार के निकट के प्रान्तों में आज भी नशाबन्दी लागू नहीं है उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है बंगाल और उड़ीसा में नहीं है। आज भी बिहार में अवैध ढंग से शराब तैयार की जाती है और शराब को वहां के लोग व्यवहार में लाते हैं। दूसरे राज्यों से, चोर बाजारों से शराब बिहार राज्य में आ जाती है। इस नशाबन्दी को रोकने के लिए इन्होंने जो निर्णय लिया उसका लाभ तो राज्य को नहीं हुआ, बल्कि 40 हजार लोग जो इस रोजगार में लगे थे, बेकार हो गये। इसी तरह से जो रुपया केन्द्रीय सरकार से सहायता की मद में मिला था, उसका ये उपयोग नहीं कर सके। अगर पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों को देखा जाए तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस तरह से श्री भगवत झा आजाद ने और कई मित्रों ने भी कहा है, जैसा प्रति वर्ष जो इनको केन्द्रीय सरकार से योजना की स्वीकृति मिली थी, वह खर्च करने में भी विफल रहे हैं। 1977-78 में 309 करोड़ रु० की राशि स्वीकार की गई थी और इन्होंने उपयोग किया सिर्फ 275 करोड़ रु० 1978-79 में 352 करोड़ रु० की स्वीकृति मिली थी, खर्च किए इन्होंने 299 करोड़ रु० और इस वर्ष 1979-80 के लिए 387 करोड़ रु० की स्वीकृति मिली है, इन्होंने जनवरी में 129 करोड़ रु० खर्च किया है, मार्च में कितने दिन बाकी रहे गए हैं, पता नहीं ये रुपयों का कितना उपयोग करेंगे।

इसी तरह से जहां ये आन्तरिक साधन जुटाने में विफल रहे हैं, वहां बिहार की जनता पार्टी की सरकार को केन्द्रीय सरकार से जो अंश-दान मिला, उसका भी उपयोग करने में विफल रहे हैं, जिसका कि कुप्रभाव हमारे बिहार प्रांत पर पड़ा है।

सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जब योजना बनाते हैं तो उसमें बिहार के भौगोलिक दृष्टिकोण से वहां के पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जाए और जितना भी उस प्रदेश का हिस्सा हो, उसको दिया जाए, जोकि उसको नहीं दिया जाता है।

दूसरी बात, हमारा बिहार प्रदेश खनिज द्रव्यों से भरा हुआ है। वहां पर लोहा है, कोयला है, अबरक है, जिसकी राज्य को रायल्टी मिलती है। मैं वित्त मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि आज कोयले का दाम बढ़ रहा है, लोहे का दाम बढ़ा है, अबरक का दाम बढ़ा है, परन्तु उनकी रायल्टी की दर नहीं बढ़ती है, इस रायल्टी की दर को भी इस मद के साथ जोड़ा जाए, ताकि हमारे प्रदेश को रायल्टी की मद में अधिक से अधिक पैसा मिले और हम अपने राज्य का विकास कर सकें। जो हमारे प्रदेश पर एक पिछड़ेपन का कलंक लगा है, उस को मिटाकर जहां हम नीचे से दूसरे स्थान पर है, वहां हम ऊपर से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएं और भारतवर्ष में पहला स्थान हमारा हो, ऐसा मौका हमें दें। इस काम में सहयोग दें, क्योंकि हमारे बिहार प्रांत में एक पिछड़ेपन की आग भड़क रही है, जो कि जनता पार्टी के शासन में ज्यादा बढ़ी। सब के पीछे एक ही कारण है-हमारे यहां मजदूरों की हालत बहुत खराब है, नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या है और वह भयानक रूप धारण करती जा रही है। यही कारण है कि सन् 1974 में बिहार प्रदेश में आन्दोलन खड़ा किया गया और बिहार के नौजवानों को उकसाया गया, उनको प्रलोभन दिया गया कि हम आपको रोजगार देंगे। परन्तु जनता पार्टी के शासन में सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई है उन नौजवानों की, जिन नौजवानों के कन्धे पर चढ़ कर जनता पार्टी शासन में आई थी।

[श्री कृष्ण प्रताप सिंह]

उस वक्त हमारे बिहार प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया गया था, ऐसे क्रांतिकारी कदम भी उठाये जा रहे थे जिनसे हमारे प्रदेश की तरक्की हो। जो पिपरा की घटना अब बिहार में घटी, ऐसी घटनाएं उस समय नहीं घट रहीं थीं, किसी जमींदार की हिम्मत नहीं थी कि वह किसी भी मजदूर पर उंगली को उठा दे, लेकिन आज, जनता पार्टी के राज में बेलछी से लेकर पिपरा तक जो काण्ड हुआ है यह उसकी एक शृंखला हैं और इसी वजह से हमारे मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है।

यह सौभाग्य की बात है कि इसको बिहार के वासियों ने समझा है और उन्हीं की वजह से यह 20 सूत्री कार्यक्रम अब लागू होगा और जो हमारे बेरोजगार हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, उनको मौका मिलेगा अपना भविष्य सुधारने के लिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री समीनुद्दीन (गोड्डा) . सभापति महोदय, बिहार के बजट की ताईद करते हुए मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जनता पार्टी के शासन-काल में बिहार में मौसमे-बहार नहीं, बल्कि मौसमे-खिजां था। इसी सूरते-हाल को देख कर वहां के अवाम ने यह फैसला किया कि बिहार उजड़ रहा है, विधि व्यवस्था बिगड़ गई है, अफसर गंदे हो गये हैं और यह सब कुछ तब तक ठीक नहीं हो सकता है, जब तक कि कोई स्थायी सरकार नहीं लाई जाती। वहां के हिन्दुओं और मुसलमानों ने यह फैसला किया कि इन्दिरा गांधी की सरकार बनाई जाये और इन्दिरा सरकार के हाथ मजबूत किये जायें, जिस का नतीजा आप देख रहे है कि आज सदन में इन्दिरा की अकसरियत है।

बिहार में कानून की व्यवस्था बिगड़ने और अफसरों के गंदे होने का असर खासकर गरीबों पर पड़ा है, हरिजनों और मुसलमानों पर पड़ा है। मैं चन्द मिसालें आप के सामने पेश करूंगा, जिस से आप को मालूम हो जायेगा कि किस तरह से हरिजनों और मुसलमानों पर जुल्म ढाये गये है और किस तरह से गरीब भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।

अभी अभी हमारे क्षेत्र के चार अंचलों—महागामा, सन्हौला, घुरैया और पतारगांवा— में 70 डकैतियां हुई हैं। वहां एक बस्ती में दस दस और बारह बारह डकैतियां होती हैं। यह डकैतियां अमीरों के यहां नहीं, गरीबों के यहां होती हैं और उन में से 75 फीसदी डकैतियां कमजोर वर्ग एवं मुसलमानों के घरों में होती हैं। मैंने इस की रिपोर्ट एस पी, साहबगंज और भागलपुर से की है कि वह मुखिया के साथ इस की एनक्वायरी करें। लेकिन उन्हो ने एनक्वायरी नहीं की और भ्रष्ट दरोगा जमादार से पूछ कर चले गये। ऐसा लगता है कि गुंडों और लूटेरो से पुलिस का साज-बाज है। श्री भगवत झा आजाद ने ठीक ही कहा है कि रात रात भर लोग गांव में नहीं सोते हैं। मुहर्रम को लगभग तीन चार महीने गुजर गये हैं। काला ढुमरिया, थाना महगामा (सन्थाल परगना) के एक मैदान में कब्रिस्तान, पीरस्तान और करबला मैदान है, मगर वहां के तखरीब पसंद अनासिर ने वहां झोपड़े बना डाले हैं और उन लोगों, मुसलमानों को पहलाम नहीं करने दिया गया है। आज तक वहां झंडा खड़ा हुआ है। मैं ने डी० सी० साहब, दुमका और दूसरे अफसरान से कहा कि इन हालात में दंगा-फसाद हो सकता था? उन लोगों को गैर-कानूनी तरीके से पहलाम नहीं करने दिया गया है। क्यों नहीं ऐसी सूरत में मेल-मिलाप कराकर पहलाम कराया जाता है?

मैं साफ तरीके से कह देना चाहता हूं कि आसाम की तहरीक से सारा हिन्दुस्तान लरज रहा है और आज वह बीमारी संथाल परगना में भी संथालियों और गैर-संथालियों के बीच जोरों पर चली हुई है, संथाल लोग गैर-संथालियों को चाहे वे गरीब हों और चाहे अमीर हों, वहां से गैर कानूनी तौर पर उजाड़ रहे हैं और उनको वहां से निकालना चाहते हैं। 17 तारीख को संथाल हंगामा करने के लिये इकट्ठा हो रहे हैं जिसके बारे में मैंने गर्वनर साहब को लिख भी दिया है कि एक हंगामा होने वाला है, लूट और आगजनी होने वाली है और इस तरफ वे ध्यान दें। जमशेदपुर में मुसलमानों पर जुल्म ढाए गये, बहु-बेटियों और मासूम बच्चों को जलाया गया और उल्टे उनकी बन्दूकें भी जब्त कर ली गयीं और उनको गिरफ्तार भी किया गया। इस तरह की विधि व्यवस्था का खेमियाजा ज्यादातर गरीबों को, हरिजनों को और मुसलमानो को भुगतना पड़ रहा है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारा क्षेत्र अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित हो चुका है। इसके पेशे नजर फैमिन एक्ट के मुताबिक वहां पर लोगों को काम मिलना चाहिए, लाल कार्ड मिलने चाहिए। हार्ड मैनुअल और लाइट मैनुअल काम लोगों को देना चाहिए और जो अपाहिज हैं, उनको लाल कार्ड दिया जाना चाहिए और राशन का बटवारा होना चाहिए मगर ये सारी की सारी चीजें कुछ भी वहां नहीं हो रही हैं।

चन्द चीजें मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मैं पहली बार आज पार्लियामेंट में बोल रहा हूं। हमारे क्षेत्र में ऐसी-ऐसी उल्टी बातें हुई हैं जैसे मधुपर में एक टंकी तो बना दी गई है और शहरों में पानी देने के लिए पाइप लाइनें भी डाल दी गई है लेकिन उस टंकी में कहां से पानी आएगा, उसका पता नहीं है। लाखों रुपया खर्च करके एक बड़ी टंकी बना दी गई है और पड़ैया और गोड्डा में नहर खोदी गई है। लेकिन पानी कहां से आवेगा, वह पता नहीं है। ये सारी चीजें पिछली सरकार की नाअहलियत का सबूत है और इस नाअहलियत को वहां की जनता ने समझ लिया था कि अगर यह सरकार बरकरार रही, तो

हिन्दुस्तान चूर-चूर हो जाएगा और तबाह और बरबाद हो जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेसजन यह न सोचें कि हमारी बातों में आकर हमारे प्रोपेगन्डे की वजह से लोगों ने वोट दिया है। बल्कि उन्होंने जनता पार्टी की नाअहलियत की वजह से कांग्रेस को वोट दिया है और जनता सरकार को गिराया है। आज मैं अपनी सरकार से कहता हूं कि उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए युद्ध स्तर पर हालात में अगर सुधार नहीं किया गया, तो फिर जनता दूसरा फैसला भी कर सकती है।

इन शब्दों के साथ में अदब के साथ सदन की तवज्जह इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं कि मैंने जो बातें कही हैं उन पर सरकार ध्यान दे और उनका हल निकाले।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अभी हमारे बिहार के नेताओं और दूसरे साथियों ने भाषण दिये और उनको मैंने बहुत गौर से सुना। सब ने यह कहा है कि जितनी सारी एट्रोसिटीज हुई हैं, वे सब लोक दल और जनता पार्टी की सरकारों के इशारे पर की हैं। कुछ ऐसा कलंक का टीका इन माननीय सदस्यों ने लगाया है।

मैं एक बात आप से पूछना चाहता हूं कि जब पिपरा की घटना घटी थी तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि यह जनता पार्टी और लोक दल के, कुशासन का फल था और जब हम लोगों ने सत्ता संभाली और बेलछी कांड हुआ था, तो हम ने कभी नहीं कहा था कि कांग्रेस के कुशासन का फल है।

दूसरी बात यह कही गई कि जब कांग्रेस की हकूमत थी तो हरिजन और आदिवासी बिल्कुल निश्चिंत थे और मैं यह बता दूं कि श्री केदार पांडे वहां के मुख्य मंत्री रहे हैं, श्री हरिनाथ मिश्र बिहार के स्पीकर रहे हैं, आप इन से पूछिये सब से पहले 1970 में रूपसपुर कांड हुआ था जिस में 13 संथाल आदिवासी मारे गये थे और मारने वाले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु और उन के परिवार के लोग थे। कह दो कि गलत बात है। वे आप की पार्टी के थे। हम ने सुना है कि सुधांशु जी मर गये हैं। लेकिन वे अभियुक्त थे और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी तक मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है।

आज हरिजन अपने अधिकारों के लिये जागरूक है। अगर उसे उस के अधिकार अहिंसा के बल पर नहीं दिए जायेंगे तो वह हिंसा के बल पर उन्हें प्राप्त करेगा। इस को कोई रोक नहीं सकता है। चाहे वह इस दल की सरकार हो, चाहे उस दल की सरकार हो। उस में आज जागरूकता आई है।

आप उन पर अत्याचारों की चर्चा करते हैं। मैं आप को बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु में 40 हरिजन मारे गये, उनके घर जला दिये गये लेकिन उन के बारे में इस हाउस में कोई डिस्कसन नहीं। वह चीज हमारे नालिज में जब आयी जब कि हरिजन और आदिवासी आयोग की रिपोर्ट यहां पेश हुई। इसलिये मैंने आप से कहा कि चाहे कोई भी हुकूमत हो अब हरिजन और आदिवासी को कोई दबाने वाला नहीं है। चाहे यह भारत सरकार की हुकूमत हो, अगर इस ने भी उन के प्रति उपेक्षा बरती तो हम विश्व की संसद् में इस मामले को ले जायेंगे, लेकिन बेलछी, पिपरा, रूपसपुर के काण्डों को हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं।

मैंने सवेरे में एक पत्र उठा कर जिक्र किया था। 6 मार्च को मुंगेर जिलान्तर्गत सरमतुहां में 50 आदिवासियों ने जाकर के पूरी मुसलमान बस्ती को घर लिया और लूटा। हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री रियासत हुसैन के लड़के को बन्दूक के कुन्दे से मारा, हमारे लोक दल के कार्यकर्ता मुहम्मद शहीद के लड़के को पीटा। इतना ही नहीं जो सबसे शर्म की बात वहां हुई वह यह थी कि एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया गया जिससे उसी समय उस का अबार्शन हो गया। आप इस सारी घटना का पता लगाइये, आप अपने सी० बी० आई० के लोगों से कहिये कि पता लगायें। अगर मैं आपकी पार्टी का नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि हमें बदनाम किया जा रहा है। हमारे यहां के डमरलाल जी बैठे हुए हैं। शायद इन के यहां के मुखिया ने इन को कहा होगा कि इन के यहां भी रानीगंज प्रखंड के परिहारी गांव में 28 हरिजनों के घरों को जला दिया गया। यह खबर आप बिहार के आर्यावर्त में पढ़िये।

11 मार्च को सहर्षा जिले के बीरा थाना में एक परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गयी। 12 मार्च को पटना में, जहां कि राजधानी है, जहां राष्ट्रपति शासन का प्रमुख बैठता है, वहां एक पुलिस वाले ने सवेरे सात बजे एक रिक्शा चालक की पत्नी के साथ बलात्कार किया और वह पकड़ा गया।

सभापति महोदय, मैं आप से कहना चाहूंगा कि हरिजन, आदिवासी और मुसलमानों के नाम पर आप बहुत दिनों तक जिंदा रहने वाले नहीं हैं। आप कहते हैं कि कर्पूरि ठाकुर ने जातिवाद फैलाया। आप तीस साल तक क्या करते रहे? हरिजनों का वोट मांगना था तो जगजीवन राम जी मांग कर ले आयेंगे, ब्राह्मणों का वोट लेना था तो ललित नारायण मिश्र ले आयेंगे यादवों का वोट लेना था तो श्री रामलखन सिंह यादव ले आयेंगे। ये सब रास्ते आपके दिखाये हुए हैं, ये सब कुकर्म आप के किये हुए हैं। इसलिये आप हम लोगों को अब मत समझाइये।

बिहार में सब से अधिक बाढ़ का प्रकोप है, सूखे की विभीषिका होती है। बिहार में ठंडक और गर्मी भी बहुत होती है। बिहार में खनिज है तो दूसरी तरफ गरीबी है। बिहार में राजनीतिक चेतना है तो दूसरी तरफ रूढ़िवादिता भी है। बिहार में एक व्यक्ति के पास में हजारों एकड़ जमीन है जो कि सब के सब आप की पार्टी के हैं और दूसरी बिना जमीन वाले गरीब हरिजन लोग भी वहां हैं। एक तरफ गरीब की हत्या होती है तो दूसरी तरफ नक्सलाइटस सिर उठा रहे हैं। चाहे यह गलत तरीके से हो लेकिन गरीब के हक दिलाने के लिए वे खिड

[राम विलास पासवान]

उठा रहे हैं। बिहार आज ऐसे प्वाइंट पर पहुंच गया है कि जहां पर अहिंसात्मक तरीके से अगर समस्या का निदान नहीं हुआ तो हिंसा की ज्वाला भड़केगी। इसलिये आप किसी पार्टी को क्लेम न कीजिए। छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना आप करें, यातायात बिजली, सिंचाई का प्रबन्ध करें। पिपरा में और बेलछी में क्यों घटनायें घटीं इस वास्ते कि वहां यातायात का कोई साधन नहीं है और पुलिस तुरन्त पहुंच नहीं सकी। इस वास्ते यातायात की व्यवस्था भी आप करें। बेरोजगारी की समस्या का आप निदान करें। रेलवे का जोनल आफिस कलकत्ता में है, यू० पी० में है लेकिन हमारे यहां डी आर एम का हो आफिस है जो पोस्ट आफिस का ही काम करता है, इस वास्ते बिहार में जोनल आफिस की स्थापना आप करें। साथ ही पटना के नजदीक, भागलपुर, मुंगेर आदि के नजदीक उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने के लिए रेल पुल बनाएं और इन दोनों भागों को जोड़ने की व्यवस्था करें। हरिजनों, आदिवासियों की रक्षा का प्रबन्ध करें, इन को जमीनों से बेदखलियों को आप रोकें। ऐसा आप ने किया तभी बिहार का भला होगा, आप का भला होगा, हमारा भला होगा, देश का भला होगा।

THE MINISTER OF FINANCE AND INDUSTRY (SHRI R. VENKATARAMAN) : Mr. Chairman, Sir, I will divide the speeches that were made in the course of the debate into two broad classifications, one political and the other economic. A number of speeches were made regarding the law and order situation in Bihar and very serious allegations were made on either side of the House. But they are only allegations and allegations are no proof. The State's representative is here and I am sure he would have taken note of all these allegations made and whatever shortcomings there is in the administration of law and order situation in Bihar, they should endeavour to make it up and see that it is brought on a very high level.

My esteemed friend, Mr. Satyendra Narayan Sinha, referred to the impropriety of the proclamation issued. I have only to say that if you set bad precedents, others will follow them to their advantage. Not only that, if you sow thistles, you cannot reap figs. I would not go further into this. Within the limited time at my disposal, I shall confine myself to the problems of development of Bihar and the provisions made for it in the interim Budget.

It is true that Bihar is one among the backward States in India. At the same time if one looks at the efforts made to improve the economic conditions, it will be found that the centre has devoted more than a fair share of its resources for the development of Bihar. I will give one or two instances.

The total amount of investment in public sector in the whole of India as of 31 March, 1979 was roughly Rs. 15,700 crores and out of this a sum of Rs. 2,877 crores has been invested in Bihar alone. I am sure, nobody from Bihar can complain that the Centre has neglected Bihar. On the other hand, I beg the House that these figures should not be used against me when it comes to central investment in other States.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : We will use them sparingly.

SHRI R. VENKATARAMAN : Again if you look at the allocation for the plan for the year 1980-81,.....

PROF. MADHU DANDAVATE: (Rajapur) : You are provoking other States.

SHRI R. VENKATARAMAN : I never provoke anybody. I never knew that I provoked my esteemed friend, Mr. Dandavate. I said, in comparison, we have done very well in Bihar and we should dispel any impression that might be prevailing among the people of Bihar that they have not been done fair by the Centre. That is all my anxiety. If you look at the plan provision in the Budget documents which we have presented to the House and for which, I am seeking the approval of the House, you will find that the plan provision for 1979-80 was 356.85 crores and the plan provision that we have made for 1980-81 is Rs. 425 crores, a step up of 19% in the plan investment. It is one among the few States where the plan has gone up very high and this is because the Planning Commission and the Central Government felt that the needs of Bihar are very great and it must be so arranged that their progress comes up fast and comes equal to the other advanced States.

If you look at the break-up of these figures also, it will answer a few criticisms that have been raised. Irrigation and flood control will have Rs. 130 crores out of Rs. 425 crores. The hon. Member on the other side said that flood control has not been given enough attention and that Bihar suffers from floods on one side and drought on other. Adequate provision has been made, I should say, ample provision has been made, for flood control and irrigation. For power, Rs. 115 crores have been provided; for social services, Rs. 61 crores have been provided. Therefore, there cannot be any objection raised by anybody that provisions for Bihar in the interim Budget that has been presented are not adequate.

Connected with this is the question of drought. It is true that Bihar has been afflicted by severe drought. In order to alleviate the sufferings caused by drought, the allocation that has been made for Bihar during the year, under the normal food for work programme is 1,96,000 tonnes of foodgrains and, in addition we have also provided 1,25,000 tonnes for the special food for work programme. In fact, there cannot be any complaint that adequate steps have not been taken to alleviate the sufferings caused by drought. The overall allocation that the Government of India has made for drought relief is in addition to the normal food for work programme. We have allocated nearly another 2 lakh tonnes. In addition to 1,96,000 tonnes, we have provided another 1,25,000 tonnes for Bihar. This should take care of the situation.

Further, the Central Government have provided Rs. 10 crores as cash advance on Plan side. It is possible, in a few areas the food may not have reached. One cannot guarantee that, even though an allocation has been made, it will reach every place uniformly. If there are any such instances, we will have to take note of that and have it rectified. But it cannot be a criticism that the whole food for work programme is not adequate or it has not been properly implemented.

Then, my hon. friend, Shri Satyendra Narayan Sinha also mentioned about the supply of diesel and kerosene. In January, 1980, actually 28,000 M.T. of diesel and 13,900 M.T. of kerosene have been allotted. In February, it is 26,000 M.T. of diesel and 16,000 M.T. of kerosene.

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA : The requirement of Bihar is 70,000 M.T.

SHRI R. VENKATARAMAN : All over the country there is a shortage. Since Barauni is not working and since the major part of our refinery product is not available all over the country there is a shortage. The available material is really distributed amongst the various states in proportion to their needs. Therefore, considering the over-all shortage in the country, I would like to mention to my friend that Bihar has been treated fairly, and substantial quantities have been allocated to the Bihar state. I quite agree with him that we have not been able to meet all the demands but this is true not only of Bihar but every other state. We have not been able to meet all the needs of the states for several reasons, the most important one being the shut-down of the Assam Refinery and the Barauni Refinery.

Then, Smt. Krishna Sahi made two suggestions. One is that we should write off the debt due from Bihar. I would like to remind the Hon. Member that the debt burden of all the states was really looked into by the Seventh Finance Commission, and the seventh Finance Commission made recommendations for several States, for relief from debt. Bihar is one of the larger beneficiaries in this regard. But if you say that every year we should go on writing off the debt, it would be impossible for any Government to function.

She also mentioned about taking up, as a Central scheme, the Ganga Basin Works. I want to assure the Hon. Member that whatever funds are required for this scheme will be provided. In a planned economy it does not matter whether it is taken up by the Centre or the state. But I want to assure the Hon. Member that the requisite funds for this scheme, which is considered to be very important to both Bihar and the country, will be provided.

राम विलास पासवान : यह काम दस साल से चल रहा है।

AN HON. MEMBER: For ten years it is going on, he says.

SHRI R. VENKATARAMAN : Yes, it is a big scheme and it takes a long time. If we want to write a book, we can write a book about a scheme in two days, If we want to draw a picture, it may take only two hours but to execute a scheme it takes years.

PROF. MADHU DANDAVATE : If you are in jail, the book can be completed in a shorter time!

SHRI R. VENKATARAMAN : Yes, I have been there and I know : it is nothing new to me.

Now, Shri C. P. Verma talked about drought relief. As mentioned earlier, we have made allocations for this purpose and I would also like to assure him that if more food-grains are required for Bihar, it will be forthcoming because we do not want to stint the supply of food for any part of the country where there is drought and where the need is urgent. Fortunately, we have a sufficient buffer-stock of food and there is no reason why we should be very parsimonious in this regard.

Two other Members talked about the backwardness of Bihar, and I have dealt with it. The backwardness cannot be removed overnight. It can be done only over a period, and planned economy is one of the instruments by which we can remove the backwarndess. That is how, in the Plan, we are continuing to allocate larger and larger funds for the very backward states.

[SHRI R. VENKATAREMAF]

There was a cirticism that, for water supply, only Rs. 18 crores have been allocated. But if it is compared with the previous year's allocation, which is Rs. 13 crores, it is nearly 50% more. So, you will find that the provision has been very generous.

Lastly, I would like to say that the interim budget which has been presented here is not the finally shaped budget, except that so far as the Plan is concerned, we have made adequate provision, pending final settlement of the figures.

So far as the other aspects are concerned, the regular budget will come with adequate provisions for them and will also make necessary appropriations.

I request that the House may accept the interim budget.

MR. CHAIRMAN : I shall now put all the Cut Motions moved to the Demands for Grants on Account in respect of Bihar for 1980-81 to vote together, unless any hon. Member desires that any of his Cut Motions may be put separately.

Cut Motion nos. 9 to 20 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : I shall now put the Demands for Grants on Account in respect of Bihar to vote.

The question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar, *on account*, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1981, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 1, 3 to 8, and 10 to 28."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now, the Supplementary Demands. I shall now put all the Cut Motions moved to the Supplementary Demands for Grants in respect of Bihar for 1979-80 to vote together, unless any hon. Member desires that any of his Cut Motions may be put separately.

Cut Motions nos. 1 to 23 were put and negatited.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Supplementary Demands for Grants in respect of Bihar for 1979-80 to vote.

The question is :

"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of the Stat of Bihar, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1980, in respect of the following demands entered in the second column thereof—

Demands Nos. 1, 3 to 6, 10 to 26 and 28."

The motion was adopted.

15.52 hrs.

BIHAR APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1980*

THE MINISTER OF FINANCE AND INDUSTRY (SHRI R. VENKATARAMAN): Sir I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of a part of the financial year 1980-81.

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of a part of the financial year 1980-81."

The motion was adopted.

SHRI R. VENKATARAMAN: Sir, I introduce† the Bill.

I beg to move†:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of a part of the financial year 1980-81, be taken into consideration."

---

*Published in Gazette of India Extra-ordinary Part II Section 2, dated 15-3-80.

†Introduced/moved with the recommendation of the President.